सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

# परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 164, नई दिल्ली । शनिवार, 24 अगस्त 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है।

03 *एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल ने निभाया बेटा होने का फ़र्ज़

06 भारतीय समाज की पहचान का प्रश्न

08 संगम विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने किया मेनाल वन भ्रमण

## दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी का कहना किसी के घर से हम वाहन नहीं उठा सकते कितना सही

संजय बाटला

दिल्ली में कुछ समय पहले एक माल वाहक के लिए पंजीकृत वाहन जिसे वाहन मालिक द्वारा बिना परिवहन विभाग की इजाजत लिए गैर कानूनी तरीके से अपने मालवाहक वाहन को सवारी वाहन में बदल कर दिल्ली की सड़को से सवारी भरता नजर आया जिसकी विडियो बना कर क्षेत्र वासी ने दिल्ली यातायात पुलिस, दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा के आला अधिकारी विशेष परिवहन आयुक्त को भिजवाई। **दिल्ली की जनता को जानकर आश्चर्य होगा की उस बाबत की उस पर क्या कार्रवाई हुई पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारी का कहना था कि हमको जब वह वाहन सड़क पर चलता मिलेगा तभी उस पर कोई कार्यवाही करेंगे क्योंकि हम को किसी के घर से वाहन उठाने की इजाजत नहीं है।** यहां प्रश्न उठता है

1. जब प्रवर्तन शाखा के अधिकारी के पास भी घर से नियम / कानून के अंतर्गत गलती किए हुए वाहन जिसके सबूत उपलब्ध है को उठाने की इजाजत नहीं तो किस ताकत और किसके आदेश पर नियम और क़ानून के बाहर जाकर बल पूर्वक दिल्ली की जनता के घरों पर खड़े समय सीमा समाप्त करे हुए वाहनों को उठाकर बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द किया।

2. दिल्ली की सड़को पर बिना पंजीकरण करवाए वाहनों को सवारी भरते और उतारते सभी देखते हैं पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नजर नही आते, क्यों ?

3. दिल्ली की सड़को पर अनाधिकृत गतिविधि करते वाहन सभी को नजर आते हैं पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नहीं, आखिर क्यों ?

4. दिल्ली की सड़को पर गैर कानूनी तरीके से गैर आबधित रूटो पर वाहन चलते सभी को नजर आते हैं पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नहीं, आखिर क्यों ?

5. दिल्ली की सड़को पर बिना वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र लिए वाहन चलते सभी को दिखते हैं पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नहीं, आखिर क्यों ?

6. बिना लाइसेंस के व्यक्तियों द्वारा वाहन चलाते सभी को दिखते हैं पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नहीं, आखिर क्यों ?

7. बिना इंश्योरेंस पॉलिसी प्राप्त किए वाहन दिल्ली की सड़को पर चलते सभी को दिखते हैं पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नहीं, आखिर क्यों ?

8. निजी नंबर के वाहनों से व्यावसायिक गतिविधि करते वाहन सभी को दिखते हैं पर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नहीं, आखिर क्यों ?

9. सभी कानूनी प्रक्रिया पूर्ण किए वाहनों द्वारा छोटी सी गलती जरूर दिल्ली परिवहन विभाग के प्रवर्तन शाखा को नजर आ जाती है और उसे वार्निंग देने की जगह उसका चालान गलती के अलावा भी अनेक धाराओं को लगा कर बनाना दिल्ली परिवहन विभाग की प्रवर्तन शाखा को आता है पर पूरे तरीके से गलत वाहन नजर नही आते चालान काटने के लिए, आखिर क्यों ?

इस क्यों के पीछे को कुछ इस तरह भी जाना जा सकता है

1. दिल्ली की जनता के घर में खड़े समय सीमा समाप्त कर चुके वाहनों को अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को सुपुर्द करने से कुछ तो दोस्ती बड़ी ही होगी इसीलिए घर से वाहन उठाने की इजाजत के बिना भी बल पूर्वक वाहन उठाए और अपने प्रिय को सुपुर्द किए।

2. गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से चलने वाले वाहनों को नजरंदाज कर कुछ से दोस्ती बनती ही होगी इसीलिए वाहन बंद करने/ चालान काटने की इजाजत होते हुए भी उन्हें नजरंदाज करते हैं।

निजी कारणों, निजी दोस्ती के लिए दिल्ली की जनता से खिड़वाल करने वाली प्रवर्तन शाखा और उसके आला अधिकारियों की क्या जरूरत है दिल्ली की जनता को बड़ा सवाल ?

और उससे भी बड़ा सवाल की क्या दिल्ली की जनता इनके द्वारा किए जा रहे इन कृत्यों को कभी रुकवा सकती है जब इनके सिर पर आकाओं का हाथ हो ?

कुल मिलाकर हर तरीके से मरना और भरना तो जनता को ही है।

## वाहनों का उत्सर्जन लैब में स्वीकृत सीमा से होता है कई गुना ज्यादा, अध्ययन में चौंकाने वाले खुलासे

परिवहन विशेष न्यूज

**नईदिल्ली।** एक नए अध्ययन में पाया गया है कि वास्तविक ड्राइविंग परिस्थितियों में वाहनों का एक बड़ा प्रतिशत वाहन प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट) (PUCC) (पीयूसीसी) सीमा से अधिक उत्सर्जन प्रदर्शित करता है। अध्ययन ने PUCC निरीक्षण प्रक्रिया के पूरक के लिए नजदीकी भविष्य में रिमोट सेंसिंग का इस्तेमाल करने का आह्वान किया है।

इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांस्पोर्टेशन (अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ परिवहन परिषद) (ICCT) द्वारा दिल्ली और गुरुग्राम प्राधिकरणों के सहयोग से किए गए अध्ययन में कहा गया है कि प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) टेस्ट रियल-वर्ल्ड ड्राइविंग उत्सर्जन को प्रतिबिंबित नहीं करती है।

अध्ययन में कहा गया है कि पीयूसीसी प्रक्रिया की सीमाओं के कारण, व्यापक परिस्थितियों में रिमोट सेंसिंग द्वारा पहचाने गए उच्च-उत्सर्जक की री-टेस्टिंग (पुनः परीक्षण) करने के लिए बुनियादी ढांचा लंबे समय में स्थापित किया जा सकता है।

यह भी पाया गया कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) वाहनों में भी उच्च उत्सर्जन होते हैं। विशेष रूप से नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), जिसका मतलब है कि उन्हें दिल्ली और गुरुग्राम जैसे क्षेत्रों में जो खराब वायु गुणवत्ता से पीड़ित हैं, उन्हें प्रैक्टिकल ऑप्शन (व्यवहार्य विकल्प) या शून्य-उत्सर्जन वाहनों के लिए संक्रमणकालीन कदम के रूप में बढ़ावा देना सही नजरिया नहीं हो सकता है।

अध्ययन में पाया गया कि सीएनजी वाहनों में कुछ मामलों में, प्रयोगशाला-अनुमोदित सीमाओं की तुलना में 14 गुना ज्यादा रियल-वर्ल्ड उत्सर्जन था।

ICCT ने दिसंबर 2022 और अप्रैल 2023 के बीच दिल्ली और गुरुग्राम के आसपास 20 स्थानों पर रिमोट-सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल करके अध्ययन किया। कुल 1,11,712 (1.11 लाख) टेलपाइप उत्सर्जन माप किए गए थे। और अध्ययन किए गए वाहनों में दो और तीन-पहिया वाहन, निजी कार, टैक्सी, हल्के माल वाहन और बसे शामिल थीं।

अध्ययन के दौरान शामिल किए गए लगभग 45 प्रतिशत वाहन पेट्रोल, 32 प्रतिशत सीएनजी और 23 प्रतिशत डीजल थे।

अध्ययन के अनुसार, लेटेस्ट उत्सर्जन मानक - भारत स्टेज (बीएस) -VI के लिए उत्पादित वाहनों ने सभी प्रदूषक और वाहन प्रकारों में टेलपाइप उत्सर्जन में उल्लेखनीय सुधार दिखाया।

बीएस-VI निजी कारों से रियल-वर्ल्ड NOx उत्सर्जन में BS-IV की तुलना में 81 प्रतिशत और बसों में लगभग 95 प्रतिशत की कमी आई है। इसने बताया कि कई रियल-वर्ल्ड के उत्सर्जन निर्धारित सीमा से ज्यादा बने रहे, खासकर NOx के लिए।

अध्ययन में कहा गया है कि ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वाणिज्यिक वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन निजी वाहनों की तुलना में काफी ज्यादा है।

अध्ययन में डेटा से पता चला है कि बीएस-VI टैक्सियों और हल्के माल वाहन बेड़े ने अपने निजी वाहन में इस्तेमाल होने वाले समकक्षों की तुलना में क्रमशः 2.4 और पांच गुना ज्यादा NOx उत्सर्जन का उत्सर्जन किया।

इसी तरह, सीएनजी वाहन बेड़े ने भी उच्च NOx उत्सर्जन दिखाया। जो इस धारणा को चुनौती देता है कि सीएनजी एक स्वच्छ वैकल्पिक ईंधन था। आंकड़ों का हवाला देते हुए, अध्ययन में कहा गया है कि द्वितीय श्रेणी के हल्के माल वाहन अपने NOx प्रयोगशाला सीमा से 14.2 गुना और टैक्सी चार गुना तक उत्सर्जन कर रहे थे।

निष्कर्षों के महत्व को समझाते हुए आईसीसीटी इंडिया के प्रबंध निदेशक अमित भट्ट ने कहा कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि वायु की गुणवत्ता पर प्रभाव प्रयोगशाला से निकलने वाले उत्सर्जन से नहीं, बल्कि वाहनों को चलाने के दौरान उनसे निकलने वाले प्रदूषकों से पड़ता है।

उन्होंने कहा, "इसलिए, समय आ गया है कि हम अपने उत्सर्जन परीक्षण व्यवस्था को फिर से परिभाषित करें। और शून्य-उत्सर्जन वाहनों को अपनाने के लिए आक्रामक तरीके से आगे बढ़ें।"

अध्ययन में कहा गया है कि सीएनजी वाहनों को शून्य-उत्सर्जन वाहनों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प या संक्रमणकालीन कदम के रूप में मानना, विशेष रूप से दिल्ली और गुरुग्राम जैसे खराब वायु गुणवत्ता वाले क्षेत्रों में, सही दृष्टिकोण नहीं हो सकता है।

अध्ययन के हिस्से के रूप में, सड़क के दो छोर पर रिमोट सेंसिंग डिवाइस लगाए गए थे। जब कोई वाहन गुजरता था, तो स्पेक्ट्रोमीटर उसके टेलपाइप उत्सर्जन को कैप्चर करता था।

## दिल्ली मेट्रो की टाइमिंग में हुआ बदलाव; फेज-3 के 7 कॉरिडोर पर यात्रियों को मिलेगा फायदा

**डीएमआरसी ने फेज 3 के सातों मेट्रो कॉरिडोर पर रविवार (25 अगस्त) से ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया है। अब ट्रेनों का संचालन समय से पहले होगा। इससे यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। डीएमआरसी ने बताया कि रविवार को इन कॉरिडोर पर सेवा शुरू होने से न केवल इन कॉरिडोर के यात्रियों को बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होनेवाले छात्रों को भी लाभ होगा।**

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने फेज 3 के सातों मेट्रो कॉरिडोर पर 25 अगस्त से हर रविवार ट्रेनों के संचालन समय में बदलाव किया है। इससे इन रूटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी फायदा मिलेगा। डीएमआरसी ने बताया कि दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल, नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, मुंडका से ब्रिगेडियर होशियार सिंह और बदरपुर बॉर्डर से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) के बीच मेट्रो का परिचालन हर रविवार को अब सुबह 6 बजे शुरू हो जाएगा। इन रूटों पर रविवार को मेट्रो का परिचालन सुबह 8.00 बजे से होता है।

### तीन कॉरिडोर पर ट्रेनों का संचालन सुबह 7 बजे

वहीं डीएमआरसी ने बताया कि मजलिस पार्क से शिव विहार, बॉटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम और ढांसा बस स्टैंड से द्वारका के बीच मेट्रो का परिचालन अब हर रविवार सुबह 8 बजे के बजाय सुबह 7 बजे से शुरू होगा।

| कॉरिडोर का नाम | रविवार को वर्तमान समय | 25 अगस्त से रविवार को बदला हुआ समय |
|---|---|---|
| दिलशाद गार्डन से शहीद स्थल (Red Line) | सुबह 8 बजे | सुबह 6 बजे |
| नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी (Blue Line) | सुबह 8 बजे | सुबह 6 बजे |
| मुंडका से ब्रिगेडियर होशियार सिंह (Green Line) | सुबह 8 बजे | सुबह 6 बजे |
| बदरपुर बॉर्डर से राजा नाहर सिंह (बल्लभगढ़) (Violet Line) | सुबह 8 बजे | सुबह 6 बजे |
| मजलिस पार्क से शिव विहार (Pink Line) | सुबह 8 बजे | सुबह 7 बजे |
| बॉटेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम (Magenta line) | सुबह 8 बजे | सुबह 7 बजे |
| ढांसा बस स्टैंड से द्वारका (Grey Line) | सुबह 8 बजे | सुबह 7 बजे |

### यात्रियों के साथ छात्रों को भी होगा फायदा

डीएमआरसी ने बताया कि रविवार के लिए इन कॉरिडोर पर सेवा शुरू होने से न केवल इन कॉरिडोर के यात्रियों को बल्कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होनेवाले छात्रों को भी लाभ होगा, जो आमतौर पर रविवार को आयोजित होती हैं।

संशोधित समय से उन्हें दिल्ली-एनसीआर में अपने गंतव्य तक सहज और सुविधाजनक तरीके से पहुंचने में आसानी होगी। मेट्रो नेटवर्क के अन्य सभी कॉरिडोर पर सेवाएं नियत समय सुबह 6 बजे से शुरू होंगी।

## दिल्ली ट्रैफिक: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और NHAI ने मिलाया हाथ, नेशनल हाईवे पर यातायात कम करने के लिए कसी कमर

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर के राष्ट्रीय राजमार्ग खंडों पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ एक बैठक की।

**नई दिल्ली।** दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने शहर के नेशनल हाईवे (राष्ट्रीय राजमार्ग) खंडों पर ट्रैफिक जाम कम करने के लिए रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए हाल ही में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) (एनएचएआई) के साथ एक बैठक की।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार को हुई बैठक में स्पेशल कमिश्नर अजय चौधरी और एनएचएआई अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने ट्रैफिक फ्लो में सुधार के लिए सड़क चौड़ा करना, बस स्टॉप को स्थानांतरित (रीलोकेट) करना और स्पीड कैमरा और साइनबोर्ड लगाने सहित विभिन्न उपायों का पता लगाया।

ट्रैफिक पुलिस ने कालिंदी कुंज पर सड़क चौड़ा करने और मुकरबा चौक पर बस स्टॉप को संजय गांधी परिवहन नगर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि भीड़भाड़ कम हो सके। उन्होंने कल्याणपुरी सर्कल पर NH-24 पर स्पीड कैमरा लगाने और गाजीपुर टोल प्लाजा पर सावधानी बरतने वाले साइनबोर्ड लगाने पर भी चर्चा की।

अजय चौधरी ने NH-48 पर सुचारू यातायात आवागमन सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक मार्शल तैनात करने और उचित साइनेज लगाने का भी सुझाव दिया। अतिरिक्त सिफारिशों में मुकरबा चौक के पास NH-44 पर रंबल सट्रिप्स और आयरन ग्रिल्स लगाना, मीठापुर चौक पर साइनबोर्ड लगाना और बदरपुर फ्लाईओवर पर आयरन ग्रिल्स लगाना शामिल है।

ट्रैफिक पुलिस ने एनएचएआई से उन जगहों की डिटेल्स देने का अनुरोध किया जहां चल रहे निर्माण से ट्रैफिक में देरी हो रही है। ताकि वैकल्पिक रणनीतियां तैयार की जा सकें। उन्होंने महिपालपुर फ्लाईओवर पर रंगपुरी ट्रैफिक लाइट्स के पास एक सबवे बनाने और द्वारका रोड पर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 से NH-48 तक एक भूमिगत सुरंग बनाने का भी अनुरोध किया।

रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल कमिश्नर ने कहा, "दिल्ली में कई खंड ऐसे हैं जो राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले वाहनों से प्रभावित होते हैं। शहर भर में यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और एनएचएआई के बीच उचित संचार और समन्वय होना चाहिए।"

चौधरी ने कहा, "दिल्ली परिवहन निगम, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और NHAI जैसी एजेंसियों सहित विभिन्न हितधारकों का संयुक्त प्रयास और सहयोग दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ट्रैफिक जाम को कम करने में अहम भूमिका निभाएगा।"

एनएचएआई अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने ट्रैफिक पुलिस के प्रस्तावों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और सुझावों पर शीघ्र प्रतिक्रिया का आश्वासन दिया। यह बैठक समन्वित प्रयासों और रणनीतिक नियोजन के जरिए शहर की लगातार ट्रैफिक समस्याओं से निपटने की दिशा में एक कदम है।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

# रोहिणी नक्षत्र और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जाएगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास ने बताया कि इस साल की जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 3 :55 मिनट से शुरू होगा और यह 27 अगस्त को सुबह 5 :57 मिनट तक रहेगा।

हिंदू धर्म में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस दिन लोग व्रत रखकर और बिना व्रत के भी बड़े उल्लास के साथ भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं। इस बार 26 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर कई वर्षों के बाद ऐसा संयोग बना है जो बहुत ही दुर्लभ है। श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी तिथि, बुधवार, रोहिणी नक्षत्र एवं वृष राशि में मध्य रात्रि में हुआ था। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि इस बार जन्माष्टमी का त्योहार 26 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इस साल जन्माष्टमी पर चंद्रमा, वृषभ राशि में विराजित रहेंगे, जिससे जयंती योग का निर्माण होगा। इस योग में पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। इस साल की जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। यह दिन श्रीकृष्ण को समर्पित होता है। जन्माष्टमी के इस अवसर पर भगवान श्रीकृष्ण की पूजा-उपासना की जाती है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण के शरणागत रहने वाले जातकों को मृत्यु लोक में स्वर्ग समान सुखों की प्राप्ति होती है।

ज्योतिषाचार्य अनीष व्यास ने बताया कि शास्त्रों में इसका विशेष उल्लेख है। 'अर्द्धरात्रे तु रोहिण्यां यदा कृष्णाष्टमी भवेत। तस्यामभ्यर्चनं शौरिहन्ति पापों त्रिजन्मजम।' अर्थात सोमवार में अष्टमी तिथि, जन्म समय पर रोहिणी नक्षत्र और हर्षण योग में भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का व्रत एवं जन्मोत्सव मनाने वाले श्रद्धालुओं के तीन जन्म के पाप समूल नष्ट हो जाते हैं और ऐसा योग शत्रुओं का दमन करने वाला है। निर्णय सिंधु में भी एक श्लोक आता है- 'त्रेतायां द्वापरे चैव राजन- कृतयुगे तथा। रोहिणी सहितं चेयं विद्वद्भिः समुपपोषिता।।' अर्थात हे राजन, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि में ही विद्वानों ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी का उपवास किया था इसीलिए कलयुग में भी इसी प्रकार उत्तम योग माना जाए। ऐसा योग विद्वानों और श्रद्धालुओं को अच्छी प्रकार से पोषित करने वाला योग होता है।

**शुभ मुहूर्त**

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक अनीष व्यास ने बताया कि पंचांग के अनुसार, इस साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 26 अगस्त की रात 3:39 मिनट पर होगी। 27 अगस्त रात 2:19 मिनट पर इसका समापन होगा। ऐसे में 26 अगस्त 2024 को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा जाएगा।

**रोहिणी नक्षत्र**

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक अनीष व्यास ने बताया कि रोहिणी नक्षत्र 26 अगस्त को दोपहर 03:55 मिनट से प्रारंभ होगाऔर 27 अगस्त की दोपहर 03:38 मिनट पर समाप्त होगा।

**पूजन मुहूर्त**

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक अनीष व्यास ने बताया कि इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5251वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। कृष्ण जन्माष्टमी के पूजन का शुभ मुहूर्त 26 अगस्त को देर रात 12 बजे से 27 अगस्त की 00:44 मिनट तक है।

**सर्वार्थ सिद्धि योग**

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक अनीष व्यास ने बताया कि इस साल की जन्माष्टमी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। जन्माष्टमी पर सर्वार्थ सिद्धि योग दोपहर में 3:55 मिनट से शुरू होगा और यह 27 अगस्त को सुबह 5:57 मिनट तक रहेगा। ऐसे में भगवान श्रीकृष्ण का जन्मदिन सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जाएगा।

जन्माष्टमी का भोग

भविष्यवक्ता एवं कुंडली विश्लेषक अनीष व्यास ने बताया कि भगवान लड्डू गोपाल को माखन मिश्री का भोग बहुत पसंद है। इस वजह से जन्माष्टमी वाले दिन बाल श्रीकृष्ण को माखन-मिश्री का भोग लगाएं। इसके अलावा आप केसर वाला घेवर, पेड़ा, मखने की खीर, रबड़ी, मोहनभोग, रसगुल्ला, लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं।

**करें पूजा**

भविष्यवक्ता अनीष व्यास ने बताया कि जन्माष्टमी व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के पारण व्रत की पूर्ति होती है। इस व्रत के एक दिन पहले यानी सप्तमी के दिन हल्का और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। व्रत वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत होकर सभी देवताओं को नमस्कार करें। पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। हाथ में जल, फल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। मध्यान्ह के समय काले तिल का जल छिड़क कर देवकी जी के लिए प्रसूति गृह बनाएं। अब इस सूतिका गृह में सुंदर सा बिछौना बिछाकर उस पर कलश स्थापित करें। भगवान कृष्ण और माता देवकी जी की मूर्ति या सुंदर चित्र स्थापित करें। देवकी, वासुदेव, बलदेव, नन्द, यशोदा और लक्ष्मी जी का नाम लेते हुए विधिवत पूजन करें। यह व्रत रात 12 बजे के बाद ही खोला जाता है। इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता। फलाहार के रूप में कुट्टू के आटे की पकौड़ी, मावे की बर्फी और सिंघाड़े के आटे का हलवा खा सकते हैं।

**व्रत करने से मिलेगी पाप-कष्टों से मिलती है मुक्ति**

कुंडली विश्लेषक अनीष व्यास ने बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बन रहे दुर्लभ संयोग में पूजन का विशेष महत्व है। निर्णय सिंधु नामक ग्रंथ के अनुसार ऐसा संयोग जब जन्माष्टमी पर बनता है, तो इस खास मौके को ऐसे ही गवाना नहीं चाहिए। अगर आप इस तरह के संयोग में व्रत करते हैं तो 3 जन्मों के जाने-अनजाने हुए पापों से मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि इस तिथि और संयोग में भगवान कृष्ण का पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। व्यक्ति को भगवत कृपा की प्राप्ति होती है। जो लोग कई जन्मों से प्रेत योनि में भटक रहे हो इस तिथि में उनके लिए पूजन करने से उन्हे मुक्ति मिल जाती है। इस संयोग में भगवान कृष्ण के पूजन से सिद्धि की प्राप्ति होगी तथा सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी।

# नोएडा में रहने वाले कपल्स वाइफ के साथ बनाएं इन 4 जगहों पर घूमने का प्लान, कम पैसों में कर सकेंगे एंज्वॉय

अगर आप कम पैसे में घूमने जाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है। आज हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाने के बाद आपको अपना हनीमून याद आ जाएगा।

वैसे तो भारत में कई घूमने के बेहतरीन और शानदार जगहें हैं। क्या आप इस वीकेंड अपनी वाइफ के साथ किसी शांत और हैपनिंग प्लेस पर वेकेशन प्लान कर रहे हैं। लेकिन घूमने की बात पर सबसे पहले बजट की चिंता होती है, क्योंकि हर किसी का अपना बजट होता है। ऐसे में अगर आप कम पैसे में घूमने जाना चाहते हैं, तो यह आर्टिकल आपके लिए है।

आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको कुछ ऐसी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां पर जाने के बाद आपको अपना हनीमून याद आ जाएगा और आप इन जगहों पर बेहद कम खर्चे में आराम से घूम भी सकेंगे।

**चूका बीच**

अगर इस वीकेंड आप अपने पार्टनर के साथ किसी पानी वाली जगह या फिर बीच साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। तो आपको यूपी के पीलीभीत शहर के बाहरी जगह पर स्थिति चूका बीच पर पहुंचना चाहिए। आप गाड़ी से आराम से इस जगह तक आ सकते हैं। वहीं बरेली से यहां तक का रास्ता सिर्फ एक घंटे का है। यहां पर आप 5-6 हजार रुपए खर्च कर घूम सकते हैं।

**मोरनी हिल्स**

हरियाणा का इकलौता हिल स्टेशन मोरनी हिल्स को ऑफबीट जगह के तौर पर जाना जाता है। यहां पर आप नोएडा से 5-6 घंटे में आराम से पहुंच जाएंगे। आप वीकेंड पर पार्टनर के साथ यहां पर घूमने के लिए आ सकते हैं। आजकल कपल्स मोरनी हिल्स पर भी हनीमून के लिए पहुंचते हैं। मोरनी हिल्स में आप टिक्कर ताल, मोरनी किला, गुरुद्वारा नाडा साहिब और मनसा देवी मंदिर घूम सकते हैं।

**शिमला**

घूमने के लिहाज से शिमला भी काफी खूबसूरत जगह है। हर साल भारी संख्या में कपल्स यहां पर हनीमून के लिए आते हैं। वहीं नोएडा से यह जगह ज्यादा दूर नहीं है। गर्मियों में यह जगह घूमने के लिए बेस्ट है। अप्रैल-मई के महीने में यहां पर सबसे ज्यादा क्राउड देखने को मिलता है। यहां पर घूमने के लिए पर पर्सन 6-7 हजार रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन यहां की हसीन वादियों में घूमकर आपके सारे पैसे वसूल हो जाएंगे।

**नैनीताल**

अगर आप घूमने के लिए कोई सस्ती जगह ढूंढ रहे हैं, तो आप नैनीताल जा सकते हैं। कई कपल्स नैनीताल हनीमून मनाने के लिए आते हैं। यहां पर आप 5-6 चीजें हैं, जिनको आप अपनी पत्नी के साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि एडवेंचर के शौकीन हैं, तो नैनीताल में बोटिंग और ट्रेकिंग कर सकते हैं। बता दें कि यहां पर घूमने के लिए पर पर्सन 5-6 हजार रुपए खर्चा आएगा।

# स्टाइलिश लुक पाने के लिए साड़ी के साथ कैरी करें जैकेट, हर कोई करेगा तारीफ

क्या आपने कभी साड़ी के साथ जैकेट कैरी किया है। ऐसे में आज हम आपको जैकेट के कुछ लेटेस्ट डिजाइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको पहनकर आप परफेक्ट लुक पा सकती हैं।

हम सभी को हर मौके पर साड़ियां पहनना बेहद पसंद होता है। जिसके लिए हम अक्सर अलग-अलग डिजाइन की साड़ी को खरीदते हैं और उनको पहनते हैं। बहुत सी महिलाएं साड़ी लुक को बदलने के लिए अलग-अलग तरह की एक्सेसरीज और ब्लाउज डिजाइन भी बदलते रहते हैं। हालांकि मार्केट में आपको यह सारी चीजें रेडीमेड मिल जाएंगी।

लेकिन क्या आपने कभी साड़ी के साथ जैकेट कैरी किया है। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको जैकेट के कुछ लेटेस्ट डिजाइन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको पहनकर आप परफेक्ट लुक पा सकती हैं।

**एम्ब्राइजरी वर्क वाली जैकेट**

आप साड़ी के साथ सेम कलर वाली जैकेट पहन सकती हैं। इसके लिए आपको अलग से फैब्रिक लेना होगा। आप चाहें तो जैकेट में जगह-जगह पर मोती भी लगवा सकती हैं। इसे आपको ब्लाउज के ऊपर पहनना होता है। यदि आप थोड़ा लॉन्ग जैकेट बनवाएंगी, तो यह पहनने में काफी अच्छी लगेगी।

**गोटा वर्क वाली जैकेट**

आप सीक्वेंस और गोटा वर्क वाली जैकेट को भी साड़ी के साथ कैरी कर सकती हैं। इस तरह की जैकेट पहनने के साथ ही आपको पार्टी स्टाइल लुक मिल जाता है। इस तरह की जैकेट को आप साड़ी के साथ पहनकर शादी या पार्टी में भी जा सकती हैं। इससे आपको बढ़िया लुक मिलेगा। हालांकि आपको मार्केट से कपड़ा लेकर इस तरह की जैकेट तैयार करवानी पड़ेगी।

**कॉलर डिजाइन वाली जैकेट**

स्टाइलिश लुक पाने के लिए आप साड़ी के साथ कॉलर डिजाइन वाली जैकेट को कैरी कर सकती हैं। आपको कोट स्टाइल जैकेट बनानी होगी। साड़ी के साथ इस तरह की जैकेट काफी स्टाइलिश लगती हैं और आपके पूरे लुक को बदल देती है। आप चाहें तो साड़ी के मैचिंग फैब्रिक से इस तरह की जैकेट तैयार करा सकती हैं। साथ ही इस तरह की जैकेट में आप अलग से एक्सेसरीज या बटन लगा सकती हैं।

# घी से जुड़े मिथक, जिनकी वजह से लोग नहीं करते इसका सेवन

आयुर्वेद डॉक्टर वरलक्ष्मी यनमंद्रा के अनुसार, घी न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, इसलिए यह वात और कफ दोनों को संतुलित करता है। घी बहुत बढ़िया याददाश्त बढ़ाने वाला है और हमारे पेट के अंदर के अल्सर को ठीक करने के लिए भी सबसे अच्छा है।

घी बहुत पौष्टिक होता है, लेकिन कुछ मिथकों की वजह से लोग इसका सेवन करने से परहेज करते हैं। आज हम घी खाने से जुड़े इन्हीं मिथकों के बारे में बात करेंगे। घी खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं, जो सेहत को तंदुरुस्त कर देते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर वरलक्ष्मी यनमंद्रा के अनुसार, घी न तो बहुत गर्म होता है और न ही बहुत ठंडा, इसलिए यह वात और कफ दोनों को संतुलित करता है। घी बहुत बढ़िया याददाश्त बढ़ाने वाला है और हमारे पेट के अंदर के अल्सर को ठीक करने के लिए भी सबसे अच्छा है।

**मिथक 1: घी खाने से वजन बढ़ता है**

**तथ्य-** आयुर्वेद एक्सपर्ट ने बताया कि अगर घी को कम मात्रा में खाया जाए तो इससे वजन नहीं बढ़ता है। सही मात्रा में सेवन करने पर घी तृप्ति को बढ़ावा देता है और चयापचय में सुधार करता है, जो लोगों को अपने वजन को नियंत्रण करने में मदद करता है।

**मिथक 2: घी खाने से दिल संबंधी बीमारियां हो सकती हैं**

**तथ्य-** आयुर्वेद एक्सपर्ट ने बताया कि घी ओमेगा-3 और ओमेगा-9 जैसी स्वस्थ वसा से भरपूर होता है, जो वास्तव में इसे दिल के लिए फायदेमंद बनाता है। घी का रोजाना सेवन किया जाए तो ये हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इसे खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी मदद मिलती है।

**मिथक 3: घी में मौजूद सभी वसा सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है**

**तथ्य-** आयुर्वेद एक्सपर्ट ने बताया कि घी में मौजूद सभी वसा लाभकारी होती है। ये मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से लेकर हार्मोनल संतुलन करने तक कई शारीरिक कार्यों का समर्थन करती हैं।

**मिथक 4: डीप फ्राई करने के लिए घी अच्छा नहीं होता**

**तथ्य-** आयुर्वेद एक्सपर्ट ने बताया कि घी डीप फ्राई करने के लिए घी सबसे अच्छा होता है क्योंकि ये उच्च तापमान पर स्थिर रहता है और वनस्पति तेलों के विपरीत ऑक्सीकरण नहीं करता है।

**मिथक 5: घी को पचाना मुश्किल होता है**

**तथ्य-** घी में ब्यूटिरेट होता है, जोकि एक फैटी एसिड होता है। ये आंत के स्वास्थ्य और पाचन का समर्थन करता है, जिससे इसे कई अन्य वसा की तुलना में पचाना आसान हो जाता है।

# नया रेस्टोरेंट खोलने के दौरान वास्तु के इन नियमों का रखें ध्यान, बिजनेस में होगा फायदा

अगर आप भी नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो आपको अच्छे मुनाफे के लिए वास्तु के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आज हम आपको वास्तु के कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं।

घर हो या बाहर किसी भी स्थान पर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए वास्तु के नियमों का खास पालन करने की सलाह दी जाती है। वास्तु वह विज्ञान है, जो पंच तत्वों को कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर चाहे व्यापार में मुनाफा कमाना हो, या नौकरी को सुचारू रखना हो।

अगर आप भी नया रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं, तो आपको अच्छे मुनाफे के लिए वास्तु के नियमों का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको वास्तु के कुछ ऐसे नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनको आप नया रेस्टोरेंट बनवाते समय आजमा सकते हैं।

**रेस्टोरेंट का मुख्य द्वार**

जब भी रेस्टोरेंट के मुख्य द्वार की बात होती है, तो इस बात का ध्यान रखें कि मुख्य द्वार पूर्व या फिर उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। वास्तु के अनुसार, यह दिशाएं रेस्टोरेंट के मालिक के लिए धन और सौभाग्य लेकर आती हैं। साथ ही प्रवेश द्वार से पर्याप्त रोशनी रेस्टोरेंट के अंदर आनी चाहिए, जिससे कि सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो सके।

**रसोई की दिशा**

रेस्टोरेंट की रसोई की दिशा के बारे में बात करें, तो किचन हमेशा दक्षिण-पूर्व दिशा में होना चाहिए। क्योंकि रसोई घर में यह गैस-चूल्हा रखने की सबसे शुभ दिशा है। रसोई के आसपास बाथरूम या टॉयलेट नहीं होना चाहिए। क्योंकि इससे नकारात्मक ऊर्जा आती है और आपको नुकसान हो सकता है।

**कैश काउंटर के लिए वास्तु**

रेस्टोरेंट में पूर्व या उत्तर कोने में रिसेप्शन के पास कैश काउंटर को रखा जाना चाहिए। क्योंकि दोनों ही दिशाएं लेन-देन और धन के लिए सर्वोत्तम मानी जाती हैं। वहीं कैश काउंटर के पास किसी भी तरह के खंबे या बीम को रखने से बचें। इससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर आप सही दिशा में कैश काउंटर नहीं रखते हैं, तो आपका लाभ की जगह नुकसान भी हो सकता है।

**बैठने का स्थान**

आप रेस्टोरेंट में हमेशा ग्राउंड फ्लोर पर बैठने की व्यवस्था करें। क्योंकि हमारी संस्कृति में ग्राहकों की तुलना भगवान से होती है। ऐसे में यदि आप ग्राहकों के बैठने का सही स्थान नहीं रखते हैं, तो इसका सीधा असर आपके व्यापार में हो सकता है। इसके अलावा ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करें।

**वास्तु के अनुसार रेस्टोरेंट का बाथरूम**

वास्तु नियमों के मुताबिक रेस्टोरेंट का बाथरूम रसोई के आसपास नहीं रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि बाथरूम की दीवारें रसोई की दीवारें न छुएं। उत्तर-पश्चिम या पश्चिम दिशा में बाथरूम नहीं होना चाहिए। हमेशा दक्षिण-पश्चिम दिशा में स्टोर रूम बनवाना चाहिए। आपके रेस्टोरेंट के स्टोर रूम में आटा, अनाज या अन्य आवश्यक चीजों की कमी नहीं रखनी चाहिए।

**वास्तु के अनुसार दीवार का रंग**

वास्तु के अनुसार, रेस्टोरेंट की दीवारों का रंग भी वास्तु के हिसाब से होना चाहिए। आप अगर दीवारों पर चटख रंग जैसे पीला, नीला, हरा, नारंगी और अन्य अनुकूल रंगों का चुनाव करेंगे, तो इसका ग्राहक के मन पर सकारात्मक असर पड़ता है और रेस्टोरेंट का माहौल भी पॉजिटिव होता है। साथ ही इससे आपके बिजनेस में भी लाभ होता है।

**वास्तु अनुसार लगाएं पौधे**

अगर आप अपने रेस्टोरेंट में कुछ पॉजिटिव पौधे लगाते हैं, तो आपको जीवन में इसका फायदा देखने को मिल सकता है। रेस्टोरेंट के भीतर यह पौधे ग्राहकों को आकर्षित करता है। वहीं आप ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए रेस्टोरेंट की खिड़कियों में प्राकृतिक फूल लगा सकते हैं।

वास्तु के अनुसार आप रेस्टोरेंट में एरेका पाम का पौधा रख सकते हैं। इसके अलावा रिसेप्शन पर मनी प्लांट का पौधा रखें। रेस्टोरेंट में कृत्रिम पौधे लगाने से बचना चाहिए। क्योंकि इससे आपके रेस्टोरेंट में निगेटिव एनर्जी आती है।

# एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल ने निभाया बेटा होने का फ़र्ज़

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** एक बार फिर सीएम अरविंद केजरीवाल बेटा होने का फ़र्ज़ निभाया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से लड़कर दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों को 5 महीने से रुकी उनकी पेंशन दिलवाई है। इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए साझा करते हुए वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, भाजपा शासित केंद्र सरकार अपने हिस्से का फण्ड जारी न कर 5 महीनों से दिल्ली के 1 लाख बुजुर्गों का पेंशन रोक रखा था। दिल्ली के एक लाख बुजुर्ग पिछले 5 महीने से बहुत परेशान थे; बुजुर्गों का मानना था कि उनक बेटा अरविंद केजरीवाल जेल में है, इसलिए उनकी पेंशन नहीं आ रही है।

उन्होंने कहा कि, जेल में रहते हुए बुजुर्गों के प्यार और आशीर्वाद की बदौलत भाजपा की केंद्र सरकार से लड़कर अरविंद केजरीवाल ने एक लाख बुजुर्गों को उनकी पेंशन दिलवाई है।

वित्त मंत्री आतिशी ने साझा किया कि, दिल्ली सरकार द्वारा कल 90,000 बुजुर्गों के खाते में उनके 5 महीने की पेंशन भेजी गई, बची 10,000 पेंशन आज जारी होंगी। उन्होंने कहा कि, चाहे दिल्ली के बुजुर्गों के बेटे अरविंद केजरीवाल जेल में हो लेकिन वो बुजुर्गों के हक़ में लड़ना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि, केजरीवाल सरकार दिल्लीवालों के काम नहीं रुकने देगी, जिस तरह भाजपा शासित केंद्र सरकार से लड़कर बुजुर्गों को ये पेंशन दिलवाई है, उसी तरह लड़कर दिल्लीवालों के रुके हुए काम करवायेंगे।

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि, दिल्ली के 4 लाख बुजुर्गों को वृद्धावस्था पेंशन मिलती है। इनमें से 1 लाख ऐसी पेंशन है, जिसका कुछ हिस्सा दिल्ली सरकार से और कुछ हिस्सा केंद्र सरकार से आता है। पिछले 5 महीनों से इन एक लाख बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही थी।

उन्होंने कहा कि, इन एक लाख बुजुर्गों को पेंशन इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि जिन पेंशन का हिस्सा केंद्र सरकार से आता है उसे भाजपा शासित केंद्र सरकार ने रोक रखा था। दिल्ली के बुजुर्ग बहुत परेशान थे। ये ऐसे बुजुर्ग है जो ग़रीब परिवारों से आते है, जिनके पास इस पेंशन के अलावा कोई भी आर्थिक साधन नहीं है।

उन्होंने कहा कि, ₹मैं दिल्ली के इन एक लाख बुजुर्गों को बताना चाहती हूँ कि चाहे उनके बेटे अरविंद केजरीवाल जेल में है लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें दिल्ली के बुजुर्गों की जिन्हें वो अपना माता-पिता मानते है, उनकी चिंता लगी रहती है। पिछले कुछ महीनों में मैं जब भी उनसे

मिलने गई तो उन्होंने एक चीज हर बार पूछी है कि बुजुर्गों को पेंशन मिली या नहीं? उन्होंने हर बार चिंता जताई है कि, दिल्ली के एक लाख बुजुर्ग जो उनके माता-पिता की तरह है, उन्हें पेंशन नहीं मिली है।₹

उन्होंने कहा कि, ₹मैं इन एक लाख बुजुर्गों को बधाई देना चाहती हूँ कि, जो पेंशन अप्रैल के महीने से रुक गई थी वो अब आना शुरू हो गई है। कल से ही दिल्ली के समाज कल्याण विभाग ने इन पेंशन को बुजुर्गों के अकाउंट में भेजना शुरू कर दिया है। कल तक तक़रीबन 90 हज़ार पेंशन का ट्रांसफ़र हो चुका है बाक़ी बचे 10,000 पेंशन आज दिल्ली के बुजुर्गों के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा।₹

बता दे कि दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों की पेंशन अप्रैल महीने से ही रुकी हुई थी। इस पेंशन के एक बड़े हिस्से के रूप में प्रति पेंशनर 2200 रुपये दिल्ली सरकार और 300 रुपये केंद्र सरकार देती है। लेकिन पिछले 5 महीनों से केंद्र सरकार ये हिस्सा नहीं दे रही थी। और पेंशन के नियमों की वजह से जबतक केंद्र सरकार से उनका हिस्सा नहीं मिल जाता तबतक पेंशन जारी नहीं किया जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा अपने हिस्से का फण्ड न देने की वजह से दिल्ली के एक लाख बुजुर्गों को 5 महीने तक अपनी पेंशन का इंतज़ार करना पड़ा था।

## संविधान ने सभी को इच्छानुसार धर्म को अपनाने का अधिकार दिया है : केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले

**नई दिल्ली।** नेशनल क्रिश्चन बोर्ड द्वारा इंडियन क्रिश्चन इंट्रेप्रेन्यूर्स इंवेश्टर मीट-2024 का आयोजन कांस्टीटियूशन क्लब ऑफ इंडिया रफी मार्ग नई दिल्ली में किया गया। बोर्ड के नेशनल प्रेजीडेंट जॉन मास्कू के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भारत सरकार रामदास आठवले मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे,जिनके कर कमलों द्वारा क्रिश्चन रत्न अवार्ड 2024 का वितरण भी किया गया। इस मौके पर विभिन्न राज्यों के प्रमुख समाज सेवियों को अवॉर्ड से सम्मानित किया गया तथा व्यापारियों ने देश की उन्नति और भाईचारे की मजबूती पर अपने विचार भी प्रकट किए। इसके अलावा क्रिश्चन समुदाय पर समय-समय पर होने वाले सामाजिक अत्याचार को रोकने के लिए भी विचार विमर्श किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व चेयरमैन तनवीर अहमद, सर्व समाज राष्ट्रीय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ताहिर सिद्दीकी, फेम्स ग्रुप के चेयरमैन डॉ0 मुश्ताक अंसारी, समाज सेवी जाहिद हुसैन, मोटिवेशनल स्पीकर एवं मॉडल प्रेरणा शर्मा भाटिया, मॉडल एवं इंवेट आर्गेनाईजर शालू राठी, पवन सोब्ती, लेखक विनोद शर्मा व समाज सेवी जावेद सिद्दीकी आदि गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे।

इस मौक़े पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि संविधान देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता के साथ इच्छानुसार किसी भी धर्म को अपनाने का अधिकार देता है, इसलिए धर्म के मामले में किसी भी नागरिक को हस्ताक्षेप नही करना चाहिए और ना ही किसी के धर्म को बुरा कहना चाहिए। श्री आठवले ने आगे कहा कि जिन लोगों को आज यहां अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है, अब देश व समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापारी देश की तरक्की में सहायक होते हैं व्यापारी वर्ग अगर तरक्की करेगा तो देश भी प्रगति करेगा।

# कोलकाता रेप-मर्डर केस में CJI के सवालों पर जवाब नहीं दे पाए ममता के वकील कपिल सिब्बल; शव मिलने से लेकर अब तक कब क्या हुआ?

सुषमा रानी

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर के मामले में ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। कोलकाता पुलिस की जांच रिपोर्ट और सीबीआई के सबूत के आधार पर कोर्ट में उठे सवालों के जवाब ममता सरकार की ओर से केस की पैरवी कर रहे एडवोकेट कपिल सिब्बल भी नहीं दे पाए। बॉडी देखे जाने से लेकर अब तक कब क्या हुआ यहां पढ़िए

**नई दिल्ली।** कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर से हैवानियत और मर्डर के मामले में 14 घंटे की देरी से एफआईआर दर्ज किए जाने को लेकर ममता सरकार सवालों के घेरे में है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ममता सरकार से पूछा कि एफआईआर दर्ज करने में 14 घंटे की देरी क्यों हुई।

सुप्रीम ने घटना की सूचना की पुलिस की जनरल डायरी एंट्री, अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि और एफआईआर दर्ज करने के समय में विसंगतियों पर बंगाल सरकार पर प्रश्नों की बौछार करते हुए इसे गंभीर मामला करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड देखने से पता चलता है कि पोस्टमॉर्टम होने के बाद अप्राकृतिक मौत की प्रविष्टि दर्ज की गई। जबकि पोस्टमार्टम होता है तो इसका मतलब है कि अप्राकृतिक मौत हुई है तो फिर अप्राकृतिक मौत की एंट्री उसके बाद कैसे की गई। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई है, वह आपराधिक कानून में नहीं होती।"

जस्टिस पार्डीवाला ने कहा कि उन्होंने 30 वर्षों के करियर में ऐसा नहीं देखा। कोर्ट के सवालों पर कई बार बंगाल की पैरोकारी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल निरुत्तर दिखे।

**कोलकाता रेप एवं मर्डर केस में कब क्या हुआ?**

**9 अगस्त 2024...**

- **सुबह 9:30 बजे** - आरजी कर अस्पताल में स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की प्रशिक्षु ने पीड़िता की बॉडी को दूर से देखा। उसने अपने सहकर्मियों और सीनियर डॉक्टरों को इसकी जानकारी दी। फिर सीनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रशासन को अलर्ट किया।
- **सुबह 10:10 बजे**- आरजी कर अस्पताल की पुलिस चौकी ने टाला पुलिस थाने में घटना की जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों को बताया गया कि आपातकालीन भवन की तीसरी मंजिल पर एक सेमिनार कक्ष में एक महिला अचेत अवस्था में लकड़ी के मंच पड़ी है। महिला अर्धनग्न अवस्था में है। यह जानकारी जनरल डायरी एंट्री के तौर पर दर्ज कर पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना होती है।
- **सुबह 10:30 बजे**- पुलिस अधिकारी अपराध स्थल पर पहुंचते हैं और स्थिति का जायजा लेते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया जाता है और अपराध स्थल को सील कर दिया जाता है।
- **सुबह 10:52 बजे**- अस्पताल के सहायक अधीक्षक पीड़िता के परिवार को सूचित करते हैं और उन्हें जल्दी आने के लिए कहते हैं।
- **सुबह 11:00 बजे**- होमिसाइड टीम मौके पर पहुंचती है।
- **दोपहर 12:25 बजे**- डिटेक्टिव डिपार्टमेंट की साइंटिफिक विंग के वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर घटनास्थल पर पहुंचते हैं। महिला की बॉडी की पहली फोटो दोपहर 12:29 बजे क्लिक की जाती है। फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट एक्सपर्ट भी मौके पर पहुंचते हैं। तभी कोलकाता पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर आते हैं और फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया जाता है।
- **दोपहर 12:44 बजे**- ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पीड़िता की जांच करते हैं और उसे मृत घोषित कर देते हैं।
- **दोपहर 1:00 बजे**- पीड़िता के माता-पिता अस्पताल पहुंचते हैं। अधिकारियों से मिलते हैं और 10 मिनट बाद उन्हें सेमिनार कक्ष में ले जाया जाता है।
- **दोपहर 1:47 बजे**- अस्पताल की ओर से पीड़िता का मेडिकल सर्टिफिकेट और डेथ सर्टिफिकेट पुलिस को सौंपा जाता है। पुलिस अधिकारी शरीर पर चोटों का निरीक्षण करता है, जिसमें निजी अंगों पर भी चोटें शामिल हैं। इसके बाद अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया जाता है।
- **दोपहर 3:00 बजे**- पीड़िता के परिजनों और सहकर्मी ने पहले मौखिक और फिर लिखित तौर पर मांग की कि पोस्टमॉर्टम न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में किया जाए और उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाए।
- **शाम 4:10 बजे**- न्यायिक मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे। 4:20 से 4:40 बजे के बीच पंचनामा किया जाता है। इस दौरान पीड़िता के परिवार के सदस्य और सहकर्मी मौजूद रहते हैं। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाती है।
- **शाम 6:10 बजे से 7:10 बजे**- न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में फोरेंसिक डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा पोस्टमॉर्टम किया गया। पीड़िता के परिवार के सदस्य और सहकर्मी उपस्थित रहते हैं। पोस्टमॉर्टम की वीडियोग्राफी की जाती है
- **रात 8:00 बजे**- डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचता है। रात 8:37 बजे से 8:52 बजे के बीच अपराध स्थल की 3डी मैपिंग की जाती है।
- **रात 8:30 बजे से 10:45 बजे के बीच**- फोरेंसिक टीम 40 से अधिक वस्तुओं को जांच के लिए सुरक्षित रख लेती है। इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई और स्थानीय गवाह मौजूद थे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिवार को सौंप दिया गया।
- **रात 11:45 बजे**- पीड़िता के पिता की शिकायत पर रेप और मर्डर के आरोपों में एफआईआर दर्ज की जाती है।

पुलिस का कहना है कि पीड़िता के सहकर्मियों से पूछताछ व संदिग्धों की जांच 9 अगस्त से ही शुरू हो गई थी। जबकि अगले दिन सुबह 10 बजे आरोपी संजय रॉय को जांच और गुनाह कबूलने के बाद गिरफ्तार किया गया।

कोलकाता रेप व मर्डर केस में यह अब तक की एकमात्र गिरफ्तारी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद से मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

**कोलकाता रेप एवं मर्डर केस में कोर्ट में उठे ये सवाल**

मौत की पुष्टि में तीन घंटे का समय क्यों?

सुबह 9:30 शव देखा गया और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने दोपहर 12:44 बजे मौत की पुष्टि की। यानी तीन घंटे से भी ज्यादा समय। डॉक्टर ने पुलिस को सूचना दी थी कि अचेत अवस्था में महिला पड़ी है तो फिर इलाज क्यों नहीं हुआ और अगर शव था तो उसकी पुष्टि करने के लिए डॉक्टर की जरूरत नहीं है।

**आत्महत्या का एंगल कहां से आया?**

पीड़िता के माता-पिता ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया- उन्हें सुबह 10:53 बजे अस्पताल से फोन आया। कहा गया कि आपकी बेटी बीमार है। फिर 11:15 बजे दूसरा कॉल आया, जिस पर बताया गया कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है। जबकि कोलकाता पुलिस की टाइमलाइन में सिर्फ एक कॉल का जिक्र है और आत्महत्या का नहीं, ऐसा क्यों?

**माता-पिता को इंतजार क्यों कराया?**

कोलकाता हाईकोर्ट में दायर याचिका में मृतक डॉक्टर के माता-पिता ने बताया, उन लोगों को तीन घंटे तक इंतजार कराया गया। इसके बाद बॉडी देखने की इजाजत दी गई।

पीड़िता की मां ने पत्रकारों को बताया कि उन्होंने अपनी बेटी को देखने के लिए अस्पताल प्रशासन से विनती की, उनके सामने रोईं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

पुलिस की टाइमलाइन के मुताबिक, माता-पिता को अस्पताल पहुंचने के तुरंत बाद सेमिनार कक्ष में ले जाया गया। पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने भी कोर्ट में कहा कि माता-पिता को इंतजार नहीं कराया गया था।

**एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों?**

कलकत्ता हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने सवाल उठाया कि अप्राकृतिक मौत के तौर पर मामला दर्ज हुआ। अस्पताल प्रशासन ने एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दर्ज क्यों नहीं की।

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को कोर्ट में कहा कि शव मिलने के करीब 14 घंटे देरी से एफआईआर दर्ज क्यों की गई। ऐसे मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल को तुरंत कॉलेज आना चाहिए था और एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं हुआ।

अपराध स्थल सुरक्षित पर कैसे पहुंची भीड़?

कोलकाता पुलिस के मुताबिक, क्राइम सीन को सुबह 10:30 बजे सीज कर लिया गया था, यानी शव मिलने के करीब एक घंटे बाद। 15 अगस्त को अस्पताल में भीड़ के घुसने और तोड़फोड़ करने के बाद भी कोलकाता पुलिस ने जोर देकर कहा कि अपराध स्थल सुरक्षित था।

सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के इस तथ्य को नकार दिया। सीबीआई की ओर से कहा गया कि हमने पांच दिन बाद जांच शुरू की। अपराध स्थल को बदल दिया गया है, इसलिए जांच करने में चुनौती आ रही है। एफआईआर भी अंतिम संस्कार के बाद 11:45 बजे दर्ज की गई थी।

## LG सक्सेना ने यमुना खेल परिसर के सचिव को हटाने के दिए आदेश, दो महीने में कायाकल्प करने को कहा

परिवहन विशेष

नई दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की पूर्वी दिल्ली स्थित यमुना खेल परिसर के सचिव को हटाने का आदेश दिया है। राजनिवास के अधिकारियों का कहना है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने इस खेल परिसर का दौरा किया था। वहां की व्यवस्था देखकर उन्होंने नाराजगी जताई थी।

वर्ष 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेल की तीरंदाजी और टेबल टेनिस के मुकाबले इसी खेल परिसर में आयोजित हुई थी। उपराज्यपाल ने इस खेल परिसर का अगले दो महीनों के भीतर कायाकल्प करने का आदेश दिया है। उन्होंने परिसर के प्रवेश द्वार पर स्थित भवन को क्लब हाउस के रूप में विकसित करने को कहा। इसमें रेस्तरां और मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध होगी।

**बैंक्वेट हॉल के रूप में विकसित होगा खेल परिसर**

उपराज्यपाल ने यहां बैंक्वेट हॉल की सुविधा विकसित करने को कहा है जिससे पूर्वी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को समारोह आयोजित करने के लिए बेहतर सुविधा मिल सके। खेल सुविधाओं से अलग परिसर का यह हिस्सा बाहर से आने वाले लोगों के लिए सुलभ होगा, जिससे परिसर में खेल गतिविधियों में कोई बाधा नहीं आएगी।

**अगले दो महीने में पूरा करने के आदेश**

अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों सुविधाओं से क्षेत्र के लोगों को मनोरंजन के लिए बेहतर विकल्प उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही खेल परिसर के रखरखाव और इसके विकास के लिए धन भी मिलेगा। अधिकारियों ने बताया कि उपराज्यपाल ने इन दोनों परियोजनाओं को अगले दो महीनों के भीतर पूरा करने को कहा है।

सक्सेना ने डीडीए के अधिकारियों को परिसर में विश्व स्तरीय खेल उपकरण और सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया है, जिससे कि खिलाड़ियों को अभ्यास में किसी तरह की परेशानी न हो।

## फिल्म "द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल" का " 30 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए देश भर से समर्थन का आग्रह

परिवहन विशेष न्यूज

**नई दिल्ली।** द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल की रिलीज की प्रत्याशा के साथ, देश के दो सबसे सम्मानित आध्यात्मिक नेता, धीरेंद्र शास्त्री और रामभद्राचार्य ने फिल्म के लिए एक शक्तिशाली समर्थन दिखाने के लिए आगे कदम बढ़ाया है। फिल्म के महत्वपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव को पहचानते हुए, दोनों नेता जनता से ** ० अगस्त, २०२४ को बड़े पर्दे पर इस महत्वपूर्ण कथा को देखने का आग्रह कर रहे हैं।

द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल केवल एक फिल्म नहीं है - यह आज क्षेत्र के सामने आने वाले कुछ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों की एक आंख खोलने वाली खोज है। रोहिंग्या शरणार्थियों, अवैध घुसपैठ और 'लव जिहाद' को लेकर चल रही तीखी बहस की कठोर वास्तविकताओं को साहसपूर्वक संबोधित करने वाली कहानी के साथ, यह फिल्म सार्थक चर्चाओं को बढ़ावा देने और सामाजिक-राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का वादा करती है।

फिल्म के निर्माता, जितेंद्र नारायण सिंह (वसीम रिजवी) ने नेताओं के आशीर्वाद और समर्थन के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा * _"उनका समर्थन उस कहानी के महत्व का प्रमाण है जिसे हम बता रहे हैं। हमें उम्मीद है कि उनकी कार्रवाई का आह्वान कई लोगों को इस महत्वपूर्ण कथा को देखने के लिए सिनेमाघरों में हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करेगा"

## आपातकालीन प्रतिक्रिया और सीपीआर प्रदर्शन पर विशेष सत्र पश्चिमी दिल्ली ब्रिगेड टीम

परिवहन विशेष न्यूज

COVID-19 महामारी के बाद, कई लोग दीर्घकालिक लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं। इससे नेतृत्व हुआ है गंभीर हृदयाघात से होने वाली मौतों में वृद्धि, विशेष रूप से युवा लोगों में। जवाब में, दिल्ली ब्रिगेड ने नई दिल्ली के राजौरी गार्डन में गुरु नानक पब्लिक स्कूल में एक विशेष सत्र का आयोजन किया 21 अगस्त 2024 को। इस सत्र का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और युवाओं और बच्चों को शिक्षित करना था हृदय और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। इसमें सुरक्षा संबंधी जानकारी शामिल थी, सीपीआर (कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन) की पहचान, चरण-दर-चरण क्रियाएं और प्रदर्शन।

इस सत्र में स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य के साथ 5 शिक्षकों और 50 छात्रों ने सक्रिय रूप से भाग लिया प्रबंधन समिति के सदस्य भी पूरी तरह जुटे हुए हैं। सत्र, जो सुबह 11:30 बजे शुरू हुआ और दो घंटे तक चला, यह सिर्फ एक व्याख्यान नहीं था बल्कि एक इंटरैक्टिव सीखने का अनुभव था। के अंत में सत्र में, प्रतिभागियों को प्रश्न पूछने और सही के साथ माणिकिन का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया गया प्रभावी सीपीआर परिणामों के लिए तकनीकें। प्रतिभागियों ने भी सक्रिय रूप से हैंडलिंग और शिफ्टिंग का अभ्यास किया एक दुर्घटना. सत्र छात्रों और शिक्षकों की जीवंत बातचीत और प्रतिक्रियाओं के साथ संपन्न हुआ।

पश्चिमी जिलों से दिल्ली ब्रिगेड टीम, सुश्री दविंदर कौर श्रीवास्तव, मास्टर ट्रेनर के नेतृत्व में एस दमनदीप की सहायता से प्रशिक्षक ने सत्र का संचालन किया। स्कूल प्रशासन ने इसकी सराहना की सत्र और इसे और अधिक स्कूलों में विस्तारित करने की इच्छा व्यक्त की क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण सीख है जीवन बचाने का अनुभव. दिल्ली ब्रिगेड इस जागरूकता को सभी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है जीएनसीटी दिल्ली में शैक्षणिक संस्थान, क्योंकि यह आज की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

# बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर कैश के लिए तीन-तीन लेन, फास्टैग वाले वाहनों के लिए 15 लेन

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम में बंधवाड़ी टोल प्लाजा पर अब कैश देने वाले वाहनों के लिए दोनों तरफ तीन-तीन लेन निर्धारित की जाएंगी। फास्टैग वाले वाहन 15 लेन से निकलेंगे। फास्टैग सिस्टम 31 अगस्त तक चालू करने का लक्ष्य है। फास्टैग लेन में कैश वाले वाहन न घुसें इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। फास्टैग सिस्टम के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का ट्रायल बृहस्पतिवार से शुरू कर दिया गया।

**गुरुग्राम।** बंधवाड़ी टोल प्लाजा के दोनों तरफ तीन-तीन लेन कैश वाले वाहनों के लिए निर्धारित की जाएगी। इस तरह 15 लेन से फास्टैग वाले वाहन निकलेंगे। इस बारे में टोल संचालन कंपनी ने लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया है, ताकि कैश देकर चलने वाले लोग फास्टैग वाली लेन में न घुसें।

लोगों को जागरूक करने के साथ ही फास्टैग सिस्टम के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का ट्रायल बृहस्पतिवार से शुरू कर दिया गया। ट्रायल से पता किया जा रहा है कि सिस्टम फास्टैग सही से रीड कर रहा है या नहीं। साफ्टवेयर का ट्रायल पूरा होते ही लेन से वाहनों को निकालने का ट्रायल शुरू किया जाएगा। कंपनी ने 31 अगस्त तक हर हाल में फास्टैग सिस्टम चालू करने का लक्ष्य रखा है।

**बंधवाड़ी टोल प्लाजा में कुल 21 लेन**

गुरुग्राम-फरीदाबाद रोड पर संचालित बंधवाड़ी टोल प्लाजा में कुल 21 लेन हैं। टोल प्लाजा से प्रतिदिन औसतन 50 हजार से अधिक वाहन गुजरते हैं। अभी सभी वाहनों में फास्टैग नहीं लगे हैं। ऐसे में कंपनी का मानना है कि केवल 15 लेन से फास्टैग वाले वाहनों को निकालने पर ट्रैफिक का दबाव नहीं दिखाई देगा। कैश लेन में ट्रैफिक का दबाव रहेगा क्योंकि काफी वाहनों में फास्टैग नहीं है। इसे देखते हुए लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है।

**वाहनों में फास्टैग लगाने का अनुरोध**

कंपनी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यदि सभी वाहनों में फास्टैग सिस्टम लग जाए तो पीक आवर में भी ट्रैफिक का दबाव नहीं दिखाई देगा। फास्टैग वाली लेन में ट्रैफिक का दबाव तभी दिखाई देगा जब किसी वाहन का फास्टैग काम नहीं कर रहा होगा। लोगों से अपील है कि जितनी जल्द हो अपने वाहनों में फास्टैग लगा लें अन्यथा कैश लेन में ट्रैफिक का दबाव झेलना होगा।

**फास्टैग सिस्टम विकसित होने से लोगों में खुशी**

टोल प्लाजा में फास्टैग सिस्टम विकसित होने से लोगों में खुशी का आलम है। सभी अब इसे चालू होने का इंतजार कर रहे हैं। कई साल से ट्रैफिक जाम को लोग झेल रहे हैं। सेक्टर-15 पार्ट-दो में रह रहे हरवंश वर्मा कहते हैं कि दैनिक जागरण के प्रयास से ही यह संभव हुआ है। वह फरीदाबाद में काम करते हैं। सुबह आधे घंटे पहले निकलने के बाद भी कई बार काम पर पहुंचने में देरी हो जाती है। फास्टैग सिस्टम से राहत मिलेगी।

**फास्टैग वाली लेन में कैश वाहन न करें प्रवेश**

फास्टैग वाली लेनों में कैश वाले वाहन न प्रवेश करें, इसके लिए टोल संचालन कंपनी तैयारी करे। यदि इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो समस्या बढ़ जाएगी। ऑपरेटरों के साथ वाहन चालकों की बहस होगी। ऐसे में ट्रैफिक का दबाव बढ़ जाएगा। सेक्टर-40 में रह रहे नारायण साहू का भी कहना है कि फास्टैग वाहनों के लिए निर्धारित लेनों से कैश देकर चलने वाले वाहन न प्रवेश करें। इसके लिए पुलिस को भी सक्रियता बढ़ानी होगी। बिना पुलिस की मदद के व्यवस्था बेहतर नहीं होगी।

# गाजियाबाद में दो कार्यक्रमों में हिस्सा लेने पहुंचे सीएम योगी, पुलिस ने सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम

परिवहन विशेष न्यूज

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में हैं। वो यहां दो कार्यक्रमों में हिस्सा लेने आए। इसके अलावा विधानसभा सीट के उपचुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। शहर के हिंदी भवन में योगी बैठक के लिए पहुंचे। इस बैठक में सांसद पार्षद और कई नेता भी शामिल हुए। सीएम योगी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।

**गाजियाबाद।** मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में दो कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। उनका पहला कार्यक्रम कौशांबी स्थित रेडिसन ब्लू होटल में हुआ। जबकि वह अपने दूसरे कार्यक्रम के लिए हिंदी भवन में पहुंचे।

**कुछ समय के लिए ट्रैफिक रहेगा बाधित**

मुख्यमंत्री के निकलने के दौरान कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहेगा। पुलिस ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए शहर के सात थानाक्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगाई है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के शहर आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त रहेगी।

**कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री**

पूरे रूट पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। सुबह पहले कौशांबी में कार्यक्रम के बाद सीएम एलिवेटेड रोड, राजनगर एक्सटेंशन रोड होते हुए हापुड़ चुंगी और हापुड़ रोड से हिंदी भवन आएंगे। दोपहर करीब एक बजे लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन में मुख्यमंत्री भाजपाइयों के साथ बैठक करेंगे।

**मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी-डीसीपी**

डीसीपी सिटी राजेश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री के आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था चौकस रहेगी। जिन स्थानों से मुख्यमंत्री का फ्लीट गुजरेगा वहां कुछ देर के लिए यातायात रोका जाएगा, लेकिन वाहन चालकों को कोई असुविधा नहीं होने दी जाएगी।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त दिनेश कुमार पी ने बृहस्पतिवार रात आदेश जारी कर कोतवाली, कविनगर, मधुबन बापूधाम, सिहानी गेट, नंदग्राम, इंदिरापुरम और कौशांबी थानाक्षेत्र को नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। यह पाबंदी शुक्रवार आधी रात तक लागू रहेगी।

# मॉल को बम से उड़ाने का मैसेज भेजने वाले का अब हो जाएगा पर्दाफाश! साइबर पुलिस ने रिस्पांस टीम और CBI से मांगी मदद

**गुरुग्राम के एंबिएंस मॉल में 17 अगस्त को उस समय हड़कंप मच गया था। जब यहां पर लोगों और सुरक्षा एजेंसी को बम होने की खबर मिली थी। जांच में सामने आया कि मॉल को बम से उड़ाने का मैसेज भेजने वाले ने आईपी एड्रेस को छुपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया था। साइबर पुलिस ने अब रिस्पांस टीम और CBI से इस संबंध में मदद मांगी है।**

परिवहन विशेष न्यूज

**गुरुग्राम।** एशिया के बड़े मॉल में से एक एंबियंस मॉल (Ambience Mall receives bomb threat) को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले की जांच के लिए गुरुग्राम साइबर पुलिस ने इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और सीबीआई की मदद मांगी है। अभी तक की जांच में पता चला है कि धमकी भी ई-मेल भेजने वाले ने वीपीएन का इस्तेमाल किया था।

डीएलएफ फेज तीन थाना क्षेत्र स्थित एंबियंस मॉल को 17 अगस्त को बम से उड़ने की धमकी दी गई थी। धमकी भरा एक ई-मेल मॉल प्रबंधन के पास भेजा गया था। हालांकि, पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने यहां पर जांच अभियान चलाया और कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस जांच में बताया गया था कि यह ई-मेल केवल भयभीत करने के लिए की गई थी।

इस संबंध में साइबर थाने में केस दर्ज किया गया। साइबर पुलिस मेल भेजने वाले सिस्टम के आइपी एड्रेस की तलाश में जुटी हुई थी। पता चला कि मेल भेजने वाले आरोपित ने वीपीएन का इस्तेमाल किया था। इससे उसकी लोकेशन कभी जर्मनी, कभी यूएस तो कभी क्रोएशिया की आई।

इसके बाद साइबर पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम से मदद मांगी है। यह टीम ऐसे मामलों में काम करती है। इसके अलावा सीबीआई (CBI) से भी साइबर पुलिस ने मदद मांगी है। सीबीआई भी कभी-कभी इस तरह के मामले देखती है। दोनों के सहयोग से आरोपित की तलाश की जा रही है।

**इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम**

इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम (Indian Computer Emergency Response Team) भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक कार्यालय है। यह साइबर सुरक्षा घटनाओं से निपटने के लिए नोडल एजेंसी है। यह भारतीय इंटरनेट डोमेन की सुरक्षा संबंधी रक्षा को मजबूत करता है।

**क्या होता है वीपीएन**

वीपीएन (VPN) का मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। यह कंप्यूटर और वीपीएन प्रदाता के स्वामित्व वाले रिमोट सर्वर के बीच एक डिजिटल कनेक्शन स्थापित करता है। इससे कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिबंधित साइट को भी आपरेट कर सकता है। इसका इस्तेमाल आईपी एड्रेस को भी छिपाने के किया किया जाता है। यह इंटरनेट पर वेबसाइट ब्लॉक और फायरवाल से भी बचाता है।

*"एंबियंस मॉल में बम की धमकी देने के मामले की जांच साइबर पुलिस कर रही है। आरोपित ने आईपी एड्रेस छिपाने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया था। इसके लिए इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और सीबीआइ की मदद ली जा रही है।"*

# आज एक बार फिर फ्यूल स्टेशन के लिए भूखंड योजना होगी लॉन्च, यमुना प्राधिकरण ने लिया फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

यमुना प्राधिकरण ने पहले फ्यूल स्टेशन के लिए भूखंड योजना निकाली थी जो किसी कारण से सफल नहीं हो पाई थी। अब एक बार आज फिर से प्राधिकरण फ्यूल स्टेशन के लिए भूखंड योजना निकालने जा रहा है। यह प्लान सेक्टर 18 20 व 22 डी में निकाला जाएगा। दूसरी ओर आवासीय भूखंड योजना आज समाप्त हो रही है।

**ग्रेटर नोएडा।** यमुना प्राधिकरण शुक्रवार को फ्यूल स्टेशन के लिए भूखंड योजना निकालने जा रहा है। तीन भूखंडों की योजना में नीलामी के आधार पर आवंटन होगा। योजना में आवेदन के लिए 16 सितंबर तक मौका दिया गया है।

**फ्यूल स्टेशन के लिए निकाली थी भूखंड योजना**

यमुना प्राधिकरण ने पूर्व में भी फ्यूल स्टेशन के लिए भूखंड योजना निकाली थी, लेकिन यह योजना सफल नहीं हुई। प्राधिकरण एक बार फिर सेक्टर 18, 20 व 22 डी में एक-एक भूखंड की योजना निकालने जा रहा है।

सेक्टर 18 व 22 डी में भूखंड 2100 वर्गमीटर व सेक्टर 20 में 16 सौ वर्गमीटर का है। यीडा सीईओ डा. अरुणवीर सिंह का कहना है कि भूखंड के लिए 56980 रुपये रिजर्व प्राइस रखा गया है।

**तीनों सेक्टर आवासीय श्रेणी के**

बोली के आधार पर भूखंडों का आवंटन होगा। तीनों सेक्टर आवासीय श्रेणी के हैं। फ्यूल स्टेशन से सेक्टर के लोगों को ईंधन की सुविधा आस-पास उपलब्ध हो जाएगी।

इसके अलावा यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना समाप्त होने में एक दिन बचा हुआ है। योजना शुक्रवार को समाप्त होने जा रही है, लेकिन पंजीकरण राशि के लिए सीमित पेमेंट गेटवे के कारण कई लोगों को योजना में आवेदन करने के लिए अभी भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

# मोदी दुनिया के एकमात्र ऐसे नेता हैं जो युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन, दोनों जगह हो आये हैं

**देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें रहीं। खास बात यह रही कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात के निर्देश दे रखे थे कि जब तक मोदी यूक्रेन में हैं तब तक वहां कोई हमला नहीं किया जाये।**

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का यूक्रेन दौरा कई मायनों में अहम रहा। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा भर नहीं थी बल्कि मोदी से पहले शायद ही किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने किसी युद्धग्रस्त देश की यात्रा की होगी। यही नहीं, मोदी ही पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री भी हैं जिन्होंने दो देशों के बीच चल रहे युद्ध को शांत करवाने के लिए बढ़-चढ़कर प्रयास किये हों। इसे अंतरराष्ट्रीय कूटनीति की शानदार मिसाल नहीं तो और क्या कहेंगे कि मोदी एक तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मित्रता निभा रहे हैं तो दूसरी ओर युद्ध से त्रस्त और पस्त यूक्रेन को मानवीय मदद भी मुहैया करा रहे हैं। यही नहीं, आप दुनिया के किसी भी देश को देख लीजिये या तो वह यूक्रेन के साथ है या रूस के। लेकिन मोदी के नेतृत्व वाला भारत दोनों देशों के साथ खड़ा है। मोदी से पहले दुनिया के बड़े-बड़े राष्ट्राध्यक्षों ने भले युद्धग्रस्त यूक्रेन का दौरा किया हो लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री पहले ऐसे विश्व नेता बन गये हैं जो युद्ध के बीच रूस और यूक्रेन, दोनों जगह हो आये हैं और दोनों ही जगह उन्होंने शांति का संदेश दिया है।

देखा जाये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें रहीं। खास बात यह रही कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात के निर्देश दे रखे थे कि जब तक मोदी यूक्रेन में हैं तब तक वहां कोई हमला नहीं किया जाये। इसके चलते आज यूक्रेन में दिन भर कहीं भी सायरन की आवाज नहीं सुनाई दी बल्कि अमन और चैन नजर आ रहा था जिसके चलते यूक्रेनी जनता खुश नजर आ रही थी। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जब रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था तब प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर ही युद्ध को कुछ समय के लिए रोका गया था ताकि भारतीय छात्र और नागरिक सुरक्षित रूप से वहां से निकल सकें।

आज जब गांधी और महात्मा बुद्ध की धरती के प्रधानमंत्री युद्धग्रस्त देश पहुँचे तो अमन का पैगाम लेकर गये। उनके स्वागत को आतुर हर व्यक्ति यही उम्मीद कर रहा था कि मोदी ही रूस को समझा सकते हैं और इस क्षेत्र में स्थायी शांति ला सकते हैं। खुद राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की जिस बेसब्री के साथ मोदी का इंतजार कर रहे थे और जिस तरह रूस के द्वारा दिये गये जख्मों को मोदी को दिखा रहे थे उससे साफ प्रकट हो रहा था कि जेलेंस्की की आखिरी उम्मीद भी मोदी ही हैं। जेलेंस्की के कंधे पर हाथ रखे मोदी जब यूक्रेन में तबाही का मंजर देख कर भावुक हुए तो यूक्रेनवासियों को भी लगा कि हमारे दर्द को समझने वाला कोई विश्व नेता आ गया है।

वैसे राजनीतिक हलकों में प्रधानमंत्री की कीव यात्रा को कूटनीतिक संतुलन के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि उनकी रूस यात्रा से पश्चिमी देशों में नाराजगी पैदा हो गई थी। उल्लेखनीय है कि कीव की यात्रा से लगभग छह सप्ताह पहले मोदी ने रूस की यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संघर्ष समाप्ति के मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श किया था।

# दलित वोटों की लड़ाई में सपा-बसपा आमने-सामने

मोदी सरकार ने उच्च पदों पर नौकरियों में सीधी भर्ती (लेटरल एंट्री) का अपना एक फैसला क्या वापस लिया, विपक्ष ने इसे मोदी को घेरने का हथियार बना लिया। पूरा विपक्ष अपनी पीठ ठोंक रहा है। पीठ ठोंकने वालों में यूपी के नेता मायावती और अखिलेश यादव सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव को तो लगता है कि इससे यूपी की राजनीति की धुरी ही बदल जायेगी। बसपा प्रमुख मायावती की प्रतिक्रिया आई थी कि उनके तीव्र विरोध के बाद सरकार ने सीधी भर्ती वाला निर्णय वापस लिया है। वहीं, सपा प्रमुख अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि पिछले दरवाजे से आरक्षण को नकारते हुए नियुक्तियों की साजिश आखिरकार पीडीए की एकता के आगे झुक गई। मतलब यह है कि फैसला केंद्र ने वापस लिया लेकिन अखिलेश और मायावती खुद इसका क्रेडिट ले रहे हैं। वैसे सियासत इसी को कहा जाता है।

वैसे यह पहली बार नहीं हुआ है कि परस्पर विरोधी बसपा और सपा नेताओं के सुर एक जैसे सुनाई पड़ रहे हों, इसी तरह के सुर आरक्षण में वर्गीकरण के मुद्दे पर भी देखने को मिले थे, जब बसपा ने बंद का समर्थन किया तो अखिलेश ने भी तुरंत इसके समर्थन में पोस्ट लिख कर अपना पक्ष रख दियस। बात यहीं तक सीमित नहीं है, आरक्षण से जुड़े हर मुद्दे पर मायावती और अखिलेश लगातार आक्रामक दिख रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आरक्षण के मुद्दे पर दोनों के सुर एक हैं? या दोनों के बीच एक रेस लगी हुई है कि दलितों और पिछड़ों का ज्यादा हितैषी कौन है? आखिर इस मुद्दे के जरिए मायावती और अखिलेश कौन-सी राजनीति साध रहे हैं?

इस तमाम सवालों का जवाब समझने के लिए पिछले लोकसभा चुनाव से पहले की स्थितियों और नतीजों पर गौर करना जरूरी है। यूं तो संविधान और आरक्षण बसपा का कोर मुद्दा रहे हैं लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सपा ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके पीडीए (पिछड़ा-दलित-अल्पसंख्यक) का जो नारा और इंडिया गठबंधन में शामिल होकर संविधान की रक्षा का मुद्दा भी जोर-शोर से उठाया था, उसका फायदा जब इंडिया गठबंधन को मिला तो बसपा सुप्रीमों को अपना राजनैतिक भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। इससे पहले मायावती को भी यह उम्मीद नहीं थी कि सपा का यह दांव इतना अधिक कारगर होगा। नतीजे आए तो सपा ने यूपी में अकेले 37 सीटें जीत लीं। साथ में कांग्रेस को भी छह सीटों पर जीत हासिल हुई और बसपा का सफाया हो गया। वोट प्रतिशत भी खिसक कर मात्र करीब साढ़े नौ प्रतिशत पर आ गया। इससे साफ हो गया कि सपा के द्वारा बसपा के दलित वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर ली गई है। तब से मायावती की एक ही कोशिश है कि किसी तरह अपना दलित वोटबैंक वापस लाया जाए। इसके लिए मायावती लगातार दलित हितों से जुड़े मुद्दे उठा रही हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में वर्गीकरण पर अपना मत दिया, तो मायावती की उम्मीद को पंख लग गये। मायावती ने तुरंत इस मुद्दे को लपक लिए। सबसे पहले उनकी प्रतिक्रिया आई। इसे पूरी तरह गलत ठहराते हुए उन्होंने भाजपा के साथ ही सपा-कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को भी घेरना शुरू कर दिया। वह संसद में संविधान संशोधन लाने की मांग पर अड़ गईं। इस मुद्दे पर उन्होंने दो बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सोशल मीडिया के जरिए कई बयान दिए।

- :सौजन्य :-

ईवी ड्राइव द फ्यूचर

EV Drive the Future

# जिप इलेक्ट्रिक ने ईवी फ्लीट मैनेजमेंट के लिए जिपएक्स किया लॉन्च किया

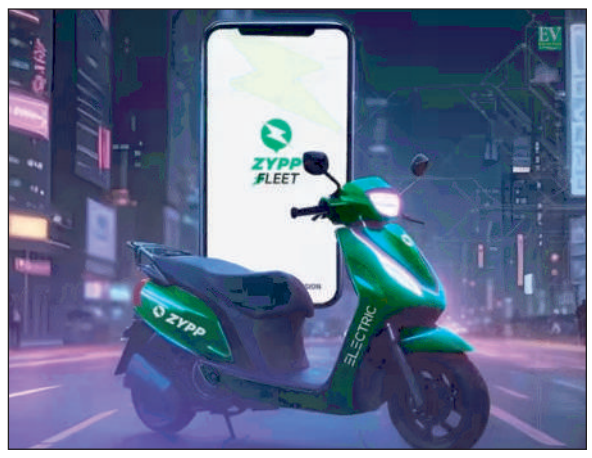




परिवहन विशेष न्यूज

जिप इलेक्ट्रिक ने ईवी सेगमेंट में एक फ्रैंचाइज़ी योजना जिपएक्स लॉन्च की है। जिप ने भारत के विभिन्न टियर 2 और टियर 3 बाजारों में फ्लीट ऑपरेटरों को अपने शहरों में जिप फ्रैंचाइज़ी मॉडल लॉन्च करने का विकल्प प्रदान करने के लिए SaaS प्लेटफ़ॉर्म बनाया है।

जिपएक्स के माध्यम से, फ्लीट ऑपरेटर, लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ और नए उद्यमियों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जिपएक्स की शक्ति का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। इसके लिए, सही ईवी खरीदने, राइडर ऑनबोर्डिंग और डीबोर्डिंग, राइडर प्रोफाइलिंग, बैटरी स्वैपिंग, टिकटिंग, डेटा विश्लेषण, बैटरी लाइफ़साइकिल मैनेजमेंट और व्यावसायिक संचालन के प्रबंधन में मदद करने के लिए उन्नत एआई, आईओटी और मशीन लर्निंग तकनीकों का उपयोग किया जाएगा।

इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर संचालन की दक्षता बढ़ाना, लागत कम करना है। कंपनी ने खुलासा किया है कि जिपएक्स फ्रैंचाइज़ी लॉन्च योजना 42 लाख के निवेश प्रस्ताव के साथ शुरू होती है और यह पहले 10 फ्रैंचाइज़ी भागीदारों के लिए 209% ROI और 68% XIRR का वादा करती है। 42 लाख का यह न्यूनतम निवेश उन्हें अपने बाजार में 40 जिप इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ शुरुआत करने में सक्षम करेगा और यह निवेश 20 महीनों में वापस किया जा सकता है, जिससे 3 साल के संचालन में कुल 88 लाख रुपये का रिटर्न मिलेगा।

जिपएक्स इलेक्ट्रिक के सीईओ आकाश गुप्ता ने कहा, यह लॉजिस्टिक्स उद्योग के लिए एक परिवर्तनकारी समाधान है। जिप में हमें अपने भागीदारों, ग्राहकों और ड्राइवर पायलटों से जिप को भारत और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर और अधिक शहरों में विस्तारित करने के लिए बहुत सारे अनुरोध मिलते हैं। जिपएक्स इसका जवाब है। हमारी उन्नत तकनीक के साथ, हमारा लक्ष्य उद्यमियों को जिपएक्स और इसके बेड़े को अधिक प्रभावी ढंग से विस्तारित करने के लिए सशक्त बनाना है, जो भारत और विदेशों में अधिक शहरों में लॉजिस्टिक्स में विद्युतीकरण और स्थिरता के व्यापक लक्ष्य में योगदान देता है।

सीईओ आकाश गुप्ता ने आगे कहा कि जिपएक्स को ईवी प्रबंधन की अनूठी चुनौतियों, जैसे उच्च अग्रिम लागत, डेटा-संचालित निर्णय लेने की कमी और वास्तविक समय ट्रैकिंग और अनुकूलन की आवश्यकता को संबोधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसे जिप इलेक्ट्रिक ने पिछले 7 वर्षों में बनाया है।

# 2025 फ्रोंक्स फेसलिफ्ट को मिलेगा ज्यादा एफिशिएंट इंजन, मारुति बना रही खुद का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम

परिवहन विशेष न्यूज

**वाहन निर्माता कंपनी मारुति अपनी खुद की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन डेवलप कर रही है। अपनी हाइब्रिड पावरट्रेन डेवलप करने के साथ ही मारुति टोयोटा द्वारा आपूर्ति की गई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप का इस्तेमाल करना जारी रखेगी। मारुति के जरिए डेवलप की गई पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन वाली गाड़ी फ्रॉन्क्स होगी। आइए जानते हैं कि इससे गाड़ियों की कीमत पर और क्षमता पर क्या असर पड़ेगा।**

**नई दिल्ली।** वाहन निर्माता कंपनी मारुति अपना खुद का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन विकसित कर रही है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन पाने वाली पहली मारुति कार फ्रॉन्क्स होगी। इसके साथ ही मारुति अपनी हाई-एंड हाइब्रिड एसयूवी के लिए टोयोटा द्वारा आपूर्ति की गई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप का इस्तेमाल करना जारी रखेंगी। टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल टोयोटा हाइराइडर, इनोवा हाइक्रॉस और मारुति इनविक्टो पॉपुलर गाड़ियों में किया जा रहा है। वहीं, अब मारुति सुजुकी अपनी खुद की नई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम को डेवलप कर रही है।

**मारुति फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट 2025 में होगी लॉन्च**

मारुति खुद का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सेटअप डेवलप कर रही है, जो मारुति की छोटी कारों के लिए उपयुक्त होगा। इसमें नए 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन के साथ जोड़ा जाएगा। इसे हाल ही में लॉन्च हुई स्विफ्ट में इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, इसकी पहली स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन पाने वाली कार फ्रॉन्क्स होगी। इसके अगले साल लॉन्च होने वाली फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट के साथ पेश किया जाएगा। वहीं, जल्द ही आने वाली बलेनो में भी नया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन मिलने की उम्मीद है।

**छोटी कारों के लिए साबित होगी गेम चेंजर**

मारुति अपनी बड़ी एसयूवी के लिए टोयोटा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करना चारी रहेगी। मारुति का नया स्टॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन सिस्टम डेवलप होने के बाद यह छोटी कारों के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। मारुति पहले से ही पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड जैसे पावरट्रेन ऑप्शन की सीरीज प्रदान करता है। इस साल के अंत तक लॉन्च होने वाली EVX SUV के साथ जल्द ही इलेक्ट्रिक पावरट्रेन भी जोड़ा जाएगा।

**मारुति स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और टोयोटा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में अंतर**

मारुति टोयोटा की सीरीज-पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम की तुलना में अपनी ही हाइब्रिड सेटअप तैयार कर रही है। टोयोटा की सीरीज-पैरेलल हाइब्रिड सिस्टम से कई फायदे मिलते हैं जैसे- वाहन को हाइब्रिड मोड, इलेक्ट्रिक-ओनली मोड और ICE-ओनली मोड। यह सेटअप काफी कॉम्लैक्स है, जिसके लिए प्लेनेटरी गियर सेट और एक बड़े बैटरी पैक जैसे एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट की जरूरत होती है। वहीं, यह ज्यादा जगह लेता है और आम तौर पर इसका उत्पादन महंगा भी होता है।

# 2024 टीवीएस जुपिटर 110 को 5 चीजें बनाती हैं खास, अपडेटेड डिजाइन से लेकर नए फीचर्स तक

परिवहन विशेष न्यूज

**2024 TVS Jupiter 110 को काफी आकर्षक डिजाइन दिया गया है। इसमें पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया फ्रंट एप्रन है। इसमें एक एलईडी लाइट बार और टर्न इंडिकेटर्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ये एलईडी हेडलैम्प और कई नए रंग विकल्पों से लैस है। साइड में शार्प लाइन्स हैं जबकि पीछे की तरफ एक पतला एलईडी टेल लैंप है। इसमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स भी शामिल हैं।**

**नई दिल्ली।** TVS Motor Company ने आखिरकार भारतीय बाजार में Jupiter 110 लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसकी शुरुआती कीमत 73,700 रुपये रखी है। अपने इस लेख में हम आपके लिए उन 5 चीजों की डिटेल्स लेकर आए हैं, जो जुपिटर 110 के बारे में जाननी चाहिए।

**डिजाइन**

जुपिटर 110 को काफी आकर्षक डिजाइन दिया गया है। इसमें पूरी तरह से नया डिजाइन किया गया फ्रंट एप्रन है। इसमें एक एलईडी लाइट बार और टर्न इंडिकेटर्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, ये एलईडी हेडलैम्प और कई नए रंग विकल्पों से लैस है।

साइड में शार्प लाइन्स हैं, जबकि पीछे की तरफ एक पतला एलईडी टेल लैंप है। इसमें इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स भी शामिल हैं। TVS ने ग्लॉस ब्लैक प्लास्टिक के उपयोग पर महत्वपूर्ण जोर दिया है। इसके अलावा, TVS का दावा है कि सीट अब अपनी श्रेणी में सबसे बड़ी है और इसमें मेटल बॉडी पैनल की सुविधा जारी है।

**इंजन अपग्रेड**

2024 TVS Jupiter में फ्यूल इंजेक्शन तकनीक वाला नया 113.3 cc एयर-कूल्ड इंजन लगा है। यह इंजन 5,000 rpm पर 7.91 bhp की अधिकतम शक्ति उत्पन्न करता है और उसी rpm पर 9.2 Nm का टॉर्क देता है।

इसमें CVT ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन बरकरार है, लेकिन अब इसमें इलेक्ट्रिक असिस्ट शामिल है जो टॉर्क आउटपुट को 9.8 Nm तक बढ़ा देता है। जुपिटर 110 को 82 किमी/घंटा की टॉप स्पीड पर भगाया जा सकता है।

**फीचर अपडेट**

जुपिटर 110 में दो हेलमेट रखने की जगह, मोबाइल डिवाइस चार्जिंग के लिए एक यूएसबी पोर्ट, एक्सटर्नल फ्यूल फिलर कैप और ये एलईडी लाइटिंग के साथ अंडरसीट स्टोरेज से लैस है।

इसके अतिरिक्त, जुपिटर 110 में नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर उपलब्ध है, जिसमें एप्लिकेशन सपोर्ट के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर है। टीवीएस ने इसमें इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, ऑटोमैटिक टर्न इंडिकेटर्स, डिस्टेंस-टू-एम्प्टी फीचर, वॉयस कमांड फंक्शनलिटी, हैजर्ड लैंप और फॉलो-मी हेडलैंप भी पेश किए हैं।

**नए कलर ऑप्शन**

TVS ने Jupiter 110 को डॉन ब्लू मैट, गैलेक्टिक कॉपर मैट, टाइटेनियम ग्रे मैट, स्टारलाईट ब्लू ग्लॉस, लूनर व्हाइट ग्लॉस और मेटेयोर रेड ग्लॉस कलर स्कीम में पेश किया है।

**वेरिएंट और कीमत**

जुपिटर 110 चार वेरिएंट- ड्रम, ड्रम अलॉय, ड्रम एसएक्ससी और डिस्क एसएक्ससी में उपलब्ध है। इनकी कीमत 73,700 रुपये से शुरू होकर 87,250 रुपये तक जाती है। दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं।

# अगले 3-4 महीनों में एंट्री मारेंगी नई कार, एमजी विंडसर ईवी से लेकर टाटा कर्वव आईसीई तक

परिवहन विशेष न्यूज

**वुलिंग क्लाउड ईवी पर आधारित MG Windsor EV इंडियन मार्केट में 11 सितंबर को शुरुआत करेगी। यह एक मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर होगी जिसमें एसयूवी और सेडान की खूबियां होंगी। Hyundai की ओर से 9 सितंबर को Alcazar Facelift लॉन्च की जाएगी। इसकी तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। इसके अलावा आईसी इंजन वाली टाटा कर्व भी 3 सितंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध होगी।**

**नई दिल्ली।** मारुति सुजुकी, हुंडई, टाटा, महिंद्रा, किआ, एमजी और होंडा जैसी कार निर्माता इस कैलेंडर वर्ष के बचे हुए समय में कई नए प्रोडक्ट पेश करने के लिए तैयार हैं। त्योहारी सीजन का लाभ उठाते हुए कंपनियां विभिन्न सेगमेंट में नई कारें लॉन्च करेंगी। हमारी लिस्ट में MG Windsor EV से लेकर Tata Curvv ICE तक शामिल है।

**MG Windsor EV**

वुलिंग क्लाउड ईवी पर आधारित, MG Windsor EV इंडियन मार्केट में 11 सितंबर को शुरुआत करेगी। यह एक मध्यम आकार की इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर होगी, जिसमें एसयूवी और सेडान की खूबियां होंगी। इसमें बड़ा इंटीरियर, पीछे की ओर झुकने वाली सीट्स, बड़ी पैनोरमिक ग्लास रूफ और कई एडवांस फीचर्स होंगे। एक बार चार्ज करने पर इसकी ड्राइविंग रेंज 500 किमी से अधिक होने की उम्मीद है। एमजी अपनी फ्लीट में इसे ZS EV से नीचे और Cloud EV के ऊपर प्लेस करेगी।

**Hyundai Alcazar Facelift**

Hyundai की ओर से 9 सितंबर को Alcazar Facelift लॉन्च की जाएगी। इसकी तस्वीरें पहले ही सामने आ चुकी हैं। डिजाइन और फीचर्स के मोर्चे पर गाड़ी में कई बदलाव होने वाले हैं। 2024 Hyundai Creta से प्रेरणा लेते हुए इस नई थ्री-रो SUV में लेवल 2 एडास और 70 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर भी मिलेंगे। इसमें 1.5L डीजल और 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन विकल्प जारी रहेंगे।

**Tata Curvv ICE**

आईसी इंजन वाली टाटा कर्व 3 सितंबर को बिक्री के लिए उपलब्ध होगी। इसमें 1.2 लीटर रेवोट्रॉन पेट्रोल, 1.2 लीटर जीडीआई पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन होगा। यह हाल ही में लॉन्च की गई कर्व ईवी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ आएगी। इंडियन मार्केट में इसका सीधा मुकाबला Citroen Besalt से होगी, इसे भी हाल ही में लॉन्च किया गया है।

# घरेलू ईवी उत्पादन हेतु केंद्र ने पीएलआई योजना के तहत 50 आवेदनों को दी मंजूरी

परिवहन विशेष न्यूज

[5:12 PM, 8/23/2024] Ev Drive The Future Ev Media: सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना के लिए वाहन निर्माताओं से प्राप्त 74 आवेदनों में से 50 को मंजूरी दे दी है। शेष 24 आवेदन प्रक्रिया में हैं।

इन स्वीकृतियों से कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की वर्तमान कम मात्रा के कारण हो रहे नुकसान की आंशिक रूप से भरपाई करने में मदद मिलने की उम्मीद है। स्वीकृत कंपनियों में बजाज ऑटो एकमात्र वाहन निर्माता है जिसे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक और तिपहिया वाहनों के लिए प्रस्तुत सभी 13 आवेदनों के लिए मंजूरी मिल गई है।

डीवीए (घरेलू मूल्य संवर्धन) आवेदन की स्थिति दिखाने वाले एक आंतरिक दस्तावेज़ के अनुसार महिंद्रा एंड महिंद्रा को 23 में से 16, टाटा मोटर्स को 27 में से 15, ओला इलेक्ट्रिक को 05 में से 04, टीवीएस मोटर को 05 में से 02 आवेदनों की मंजूरी मिली।

केंद्र की पीएलआई योजना, जिसे 2021 में 25,938 करोड़ रुपये के बजट के साथ पेश किया गया था, स्थानीयकरण और 50 प्रतिशत के घरेलू मूल्यवर्धन पर केंद्रित है।

इसे उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने और ऑटोमोटिव विनिर्माण क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

इस योजना का लक्ष्य ऑटोमोबाइल ओईएम और घटक निर्माताओं को वित्तीय प्रोत्साहन देकर बैटरी इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहनों जैसे शून्य उत्सर्जन वाहनों को बढ़ावा देना है।

पीएलआई योजना के तहत, वाहन निर्माता ईवी के वार्षिक बिक्री मूल्य का 13-15 प्रतिशत सरकारी अनुदान प्राप्त कर सकते हैं।

यह प्रोत्साहन कंपनी के राजस्व को बढ़ाने में मदद करता है और नई प्रौद्योगिकियों में निवेश की उच्च लागत को संतुलित करता है, जिससे आंतरिक दहन इंजन वाहनों और ईवी के बीच मार्जिन का अंतर कम हो जाता है।

इसके अतिरिक्त जो कंपनियां पीएलआई अवधि के पांच वर्षों के भीतर 10,000 करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री हासिल करती हैं, वे अतिरिक्त 2 प्रतिशत सरकारी सहायता के लिए पात्र होती हैं।

[6:52 PM, 8/23/2024] Ev Drive The Future Ev Media: ई-रिक्शा यूनियन के अध्यक्ष पद पर होगा त्रिकोणीय मुकाबला

उत्तराखंड के टनकपुर में ई-रिक्शा यूनियन चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। यूनियन संरक्षक हर्षवर्धन सिंह रावत ने बताया कि अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जबकि उपाध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला होगा। उन्होंने बताया कि उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद पर एक-एक प्रत्याशी ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा जबकि उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिव और कोषाध्यक्ष पद पर सीधा मुकाबला होगा। वहीं, सदस्य पद के लिए तीन लोगों ने अपनी उम्मीदवारी पेश की है। यूनियन के चुनाव एक सितंबर को होंगे।

# सन मोबिलिटी और टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए किया समझौता




परिवहन विशेष न्यूज

ब्लूव्हील्ज़ के सहयोग से एक स्थायी ऊर्जा समाधान कंपनी सन मोबिलिटी ने टाटा ऐस वाहनों के लिए एक रेट्रो फिट किट लॉन्च करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य फ्लीट ऑपरेटरों को अपने मौजूदा टाटा ऐस आंतरिक दहन इंजन या फिक्स्ड बैटरी वाहनों को सन मोबिलिटी की बैटरी स्वैपिंग तकनीक से लैस स्वैपेबल इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने में सक्षम बनाकर लॉजिस्टिक्स स्पेस में क्रांति लाना है।

लॉन्च इवेंट में टाटा ऐस के कई फ्लीट ऑपरेटर और फाइनेंसर शामिल हुए, जिसने अपने वाहनों को रेट्रोफिट करने के कई लाभों को उजागर करने के लिए एक मंच प्रदान किया। सन मोबिलिटी की स्वैपेबल बैटरी तकनीक द्वारा संचालित इलेक्ट्रिक टाटा ऐस, एक नया डीजल या सीएनजी वाहन खरीदने की तुलना में महत्वपूर्ण लागत बचत प्रदान करता है। यदि फ्लीट ऑपरेटर सीएनजी वाहनों से रेट्रो-फिटेड बैटरी स्वैपिंग ईवी में स्विच करते हैं तो वे प्रति माह लगभग 30% और डीजल वाहनों से स्विच करने पर प्रति माह लगभग 40% बचा सकते हैं।

फ्लीट ऑपरेटर अब वाहन की लंबी आयु, कम परिचालन लागत और बढ़े हुए अपटाइम का आनंद ले सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक टाटा ऐस दिल्ली क्षेत्र में नो-एंट्री घंटों के दौरान भी काम कर सकता है, जिससे उच्च उत्पादकता सुनिश्चित होती है।

रेट्रोफिटिंग न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों में रूपांतरण के लिए अनिवार्य सरकारी मानदंडों का अनुपालन करती है, बल्कि नए वाहनों में पर्याप्त निवेश की आवश्यकता के बिना व्यवसायों के मौजूदा संचालन को भी सुरक्षित रखती है। यह समाधान व्यवसायों को स्थिरता और लाभप्रदता बनाए रखते हुए नियामक आवश्यकताओं के अनुरूप बने रहने की अनुमति देता है।

इस कार्यक्रम ने वाहन बेड़े के संचालकों के साथ मूल्यवान बातचीत करने और इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव के उनके दृष्टिकोण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान किया।

सन मोबिलिटी के सीईओ अनंत बडजात्या ने कहा, "हम ब्लूव्हील्ज़ के साथ साझेदारी में टाटा ऐस वाहनों के लिए अपनी रेट्रोफिट किट पेश करने को लेकर उत्साहित हैं। हम इस पहल को एनसीआर और उसके बाहर व अन्य राज्यों में भी शुरू करेंगे।₹ ₹यह पहल सभी आकार के व्यवसायों के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सुलभ, किफ़ायती और किफ़ायती बनाने के हमारे मिशन में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

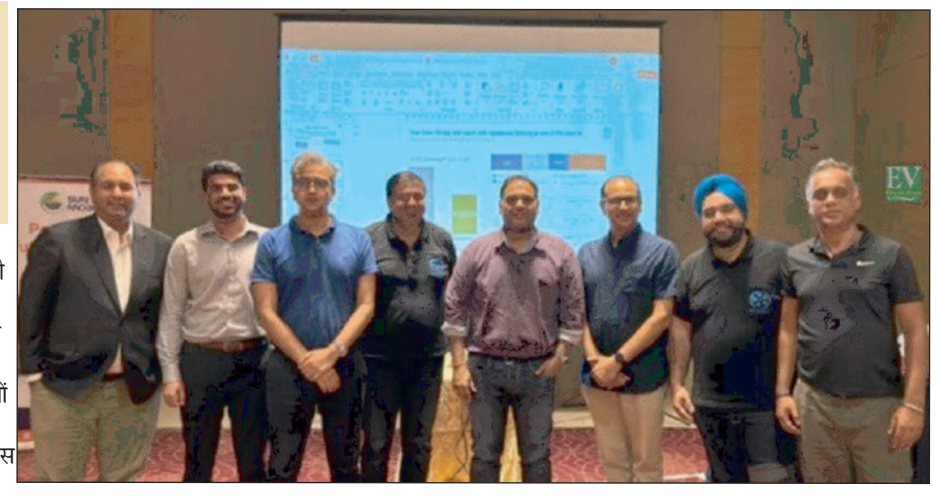

ब्लूव्हील्ज़ के संस्थापक और अध्यक्ष संजीव गुप्ता ने कहा, "स्थायित्व के लिए प्रतिबद्ध एक लॉजिस्टिक्स कंपनी के रूप में हम इस परिवर्तनकारी पहल पर सन मोबिलिटी के साथ सहयोग करने के लिए उत्साहित हैं। रेट्रोफिट किट हमारे बेड़े के संचालकों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलाव के लिए एक व्यावहारिक और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है, जो परिचालन दक्षता को बढ़ाते हुए हमारे कार्बन पदचिह्न को काफी कम करता है।"

# भारतीय समाज की पहचान का प्रश्न

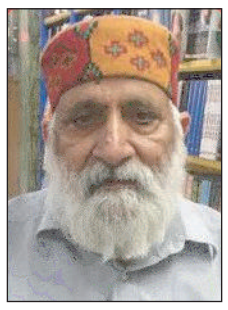

कुलदीप चंद अग्निहोत्री

**जाहिर है विभाजन का यह तरीका अवैज्ञानिक था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को इन प्रश्नों की चिंता नहीं थी'**

हिंदू की पहचान को लेकर बहस कभी बंद नहीं होती। इस बहस की शुरुआत भारत में अरबों, तुर्कों, मुगलों, पुर्तगालियों व अंग्रेजों के आने के बाद ही शुरू हुई। उससे पहले इस प्रश्न पर बहस नहीं होती थी। ये सभी विदेशी हमलावर या तो इस्लाम पंथ को मानने वाले थे या फिर ईसाई मत को मानने वाले थे। इन लोगों का सामाजिक-सांस्कृतिक व राजनीतिक जीवन इन दोनों में से किसी एक रिलीजन से समग्र रूप में संचालित होता था। उनकी पहचान के आधार भी निश्चित थे/हैं। जो व्यक्ति न्यू टैस्टामैंट में विश्वास करता है, ईसा मसीह को परमात्मा का पुत्र मानता है और चर्च में जाकर पूजा करता है, वह ईसाई है। इसी प्रकार इस्लाम पंथ को मानने वालों की पहचान भी निश्चित थी। जो व्यक्ति हजरत मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानता है, कुरान शरीफ को स्वीकारता है, मस्जिद में जाकर ईश्वर की इबादत करता है, वह इस्लाम पंथ को मानने वाला यानी मुसलमान है। जाहिर है जब एक निश्चित स्थान पर जाकर पूजा करता है तो वहां पूजा का कर्मकांड करवाने वाला भी चाहिए। इस्लाम पंथ में यह पूजा पाठ करवाने वाला मुल्ला मौलवी था। हर मस्जिद का एक मौलवी निश्चित था। उसे वायज, मीरवायज या इमाम कहा जाता था। इसी प्रकार ईसाई पंथ में पूजा का स्थान चर्च कहलाने लगा और वहां पूजा पाठ करवाने वाला व्यक्ति पादरी कहलाने लगा। लेकिन धीरे ईसाई पंथ में पूजा करवाने वाले लोगों की एक पूरी संगठित जमात खड़ी हो गई जिसका मुखिया पोप कहलाता है।

जब ये हमलावर हिंदुस्तान में आए तो सबसे पहले तो इन्होंने ईसाई पंथ व इस्लाम पंथ की तर्ज पर हिंदू को भी एक पंथ या रिलीजन ही मान लिया। उसके बाद ये लोग इस रिलीजन की पहचान करने का प्रयास करने लगे। हिंदू, जिसे इन्होंने रिलीजन समझ लिया था, उसकी पहचान समझने के लिए इन्होंने अपने अपने रिलीजन के पैमाने ही प्रयोग करने शुरू किए। लेकिन मामला पकड़ में नहीं आ रहा था क्योंकि भारतीय/हिंदू समाज को समझने के लिए जिन कारकों का प्रयोग किया जा रहा था, वे कारक ही गलत थे। यह संकट प्रत्यक्ष रूप में 1881 में सामने आया जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की कुल जनसंख्या की गणना करने के लिए एक नया विभाग स्थापित किया। जनगणना करवाना तो आसान काम ही था। लेकिन सरकार ने लगे हाथ मजहब/रिलीजन के आधार पर भी संख्या जान लेना जरूरी समझा। इसलिए जनगणना फार्म में रिलीजन को लेकर तीन कॉलम बनाए गए।

हिंदू/मुसलमान/ईसाई। जाहिर है इससे स्पष्ट पता चल गया कि हिंदुस्तान में 712 के बाद से देश में कितने लोग मुसलमान या ईसाई बन गए हैं। एटीएम (अरब-तुर्क-मुगल) मूल के मुसलमानों के सात-आठ सौ साल के शासन के दौरान कुछ करोड़ भारतीय/हिंदू भी मतांतरित हो गए थे। अंग्रेजों के शासनकाल में कुछ भारतीय ईसाई भी हो रहे थे। जाहिर है उनकी संख्या भारतीयों/हिंदुओं के मुकाबले बहुत कम ही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना और 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद अंग्रेज शासकों ने मजहब के आधार पर कुछ सीमित संख्या में भारतीयों को भी स्थानीय प्रशासन में हिस्सेदारी देना शुरू कर दिया था। तब एटीएम मूल के मुसलमानों को जिनका शासन समाप्त हो चुका था, इस बात की चिंता हुई कि संख्या के कारण अब उनको सत्ता मिलने की संभावना कम हो गई थी। इसलिए सबसे पहला काम तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों को भी अपने खेमे में जोडने या हांकने के प्रयास शुरू किए। लेकिन इसके बावजूद उनकी संख्या भला कितनी हो सकती थी? इसलिए दूसरा प्रयास किसी तरह से हिंदुओं की संख्या कम करने के प्रयास किए।

लेकिन यह काम अंग्रेज शासकों की मदद के बिना नहीं हो सकता था क्योंकि अब सत्ता तुर्कों-मुगलों के हाथ में नहीं थी, बल्कि इंग्लैंड के गोरों के हाथ में थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बकौल बाबा साहिब अंबेडकर, एटीएम मूल के आगा खान ने 1910 की जनगणना से पहले वायसराय को एक ज्ञापन दिया। उसके उपरांत ब्रिटिश सरकार ने जनगणना के प्रत्यक्ष और परोक्ष दो पैमाने निर्धारित किए। परोक्ष पैमाना तो यह था कि ब्रिटिश सरकार ने हिंदू समाज को सीमित करते हुए हिंदू केवल उसी को माना जो 'जाति व्यवस्था' से संचालित था, जबकि वस्तुस्थिति यह थी/है कि हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जाति व्यवस्था से बाहर है। एक नई अवधारणा स्थापित करने का प्रयास पहली बार हुआ कि सभी भारतीय/हिंदू जाति व्यवस्था से संचालित हैं। मूल रूप से यह अवधारणा ही गलत है। सभी भारतीय/हिंदू जाति व्यवस्था से संचालित नहीं हैं। हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जाति व्यवस्था से संचालित नहीं है। मध्य भारत, पूर्वोत्तर भारत में अधिकांश समुदाय मसलन मिजो, कुकी, खासी, गारो, निशी, शेरदुखपेन, संथाल, गोंड, पश्चिमोत्तर भारत में भोट, बलती जाति व्यवस्था से संचालित नहीं हैं। इस निराधार अवधारणा को आधार बना कर जनगणना अधिकारियों ने हिंदू को पहचानने के लिए नई कसौटियां बनाईं। जो उन कसौटियों पर पूरा नहीं उतरता था उसे हिंदू की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इनमें से एक कसौटी ब्राह्मण को लेकर थी। जनगणना करने वाले अधिकारी घर में जाकर पूछते थे कि आपके जीवन के दैनिक व्यवहार, कर्मकांड में ब्राह्मण का कोई स्थान है? यदि उत्तर नकारात्मक है तो तुरंत उस व्यक्ति को हिंदू समाज से बाहर कर दिया गया। जो हिंदू समाज जाति व्यवस्था से संचालित है, उस हिंदू समाज में तो ब्राह्मण की स्थिति पर बात की जा सकती है, लेकिन जो हिंदू जाति व्यवस्था से संचालित ही नहीं है, उनकी व्यवस्था में ब्राह्मण की स्थिति का प्रश्न कहां पैदा होता है? वह कर्मकांड के लिए ब्राह्मण को क्यों आमंत्रित करेगा? ब्रिटिश सरकार ही नहीं, देश के समाजशास्त्री अच्छी तरह जानते हैं कि ब्राह्मण जाति का अस्तित्व हिंदू समाज के केवल उस हिस्से में है जो जाति व्यवस्था से बंधा है। हिंदू समाज का बहुत बड़ा हिस्सा जाति व्यवस्था के अंतर्गत आता ही नहीं है, इसलिए वहां ब्राह्मण से जुड़े हुए जितने कर्म गिनाए गए हैं, उन सभी का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। लेकिन ब्रिटिश उपनिवेशवादियों ने बड़ी होशियारी से जाति व्यवस्था से न संचालित होने वाले हिंदू समाज को गैर हिंदू ही घोषित कर दिया।

इन मानदंडों में से एक मानदंड यह भी था कि क्या आप हिंदू देवी-देवताओं की पूजा करते हैं? जनगणना विभाग ने 'गॉड्स' शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसमें देवी-देवता दोनों ही शामिल हैं। लेकिन मूल प्रश्न है कि यह कैसे पता चलता है कि कोई देवी-देवता हिंदू है या नहीं? हिंदू गॉड्स की क्या अवधारणा है? शायद ब्रिटिश उपनिवेशवादियों का किसी से भी यह प्रश्न पूछते समय भाव यह रहा होगा कि जिन देवी-देवताओं की पूजा भारतीय/हिंदू करते हैं, उनकी पूजा आप भी करते हैं। यह ऐसा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है। आज भी यदि गणना की जाए तो भारतीय/हिंदू समाज में पूजे जाने वाले देवी-देवताओं के नामों की ही सूची तैयार करनी हो तो उसकी संख्या करोड़ों को पार कर जाएगी। इस समाज में ग्राम देवता की अवधारणा है। यह अवधारणा पूरे भारतीय समाज में मोटे तौर पर अभी भी प्रचलित है। हर गांव का एक अपना देवता भी है। इसका अर्थ हुआ जितने गांव उतने देवता। यह मामला ऐसा है कि एक स्थान का हिंदू यह नहीं जानता कि पांच सौ कोस दूर रहने वाला हिंदू किस देवता की पूजा कर रहा है। बहरहाल, जाहिर है विभाजन का यह तरीका अवैज्ञानिक था, लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों को इन प्रश्नों की चिंता नहीं थी। उन्हें हिंदू/भारतीय समाज को छोटे-छोटे समुदायों में विभाजित कर उनकी अलग-अलग पहचान स्थापित करनी थी। पश्चिमी शासकों और समाजशास्त्रियों ने हिंदू की पहचान के जो पैमाने निश्चित किए, आज भारत के समाजशास्त्री भी उन्हीं पैमानों के आधार पर भारतीय/हिंदू समाज को समझने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। उसके परिणाम सामने आ ही रहे हैं।

# आरक्षण पर 'भारत बंद'

आरक्षण पर 'भारत बंद' का आह्वान'! सफल रहा या बेअसर साबित हुआ, यह अलग मुद्दा है, लेकिन दलित-आदिवासी संगठनों ने 'भारत बंद' का आह्वान क्यों किया? यह आश्चर्यजनक लगा। क्या ऐसी नकारात्मक और विध्वंसक राजनीति भी बाबा अंबेडकर की देन है? क्या सर्वोच्च अदालत की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ का भी सामूहिक, सड़किया विरोध करना अंबेडकर की सीख है? क्या बाबा के संविधान के अनुच्छेद 16 (4) में यह उल्लेख नहीं है कि आरक्षण का उप वर्गीकरण किया जा सकता है? क्या संविधान पीठ ने विभिन्न अनुच्छेदों का हवाला देते हुए यह स्पष्ट नहीं किया है कि कोटे के भीतर कोटे की व्यवस्था भी संवैधानिक है? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने संसद के परिसर में सांसदों के एक समूह को सार्वजनिक तौर पर आश्वस्त नहीं किया था कि आरक्षण में उप वर्गीकरण के न्यायिक फैसले को स्वीकार नहीं किया जाएगा? संविधान पीठ के फैसले का किसी सरकार द्वारा ऐसा विरोध भी आश्चर्यजनक है। अलबत्ता संसद के पास ऐसी संवैधानिक शक्तियां हैं कि वह संविधान पीठ के फैसले को खारिज कर सकती है। दलित और आदिवासी संगठनों को क्या आशंका थी कि उन्होंने 'भारत बंद' का आह्वान किया और देश के कुछ हिस्सों में अराजकता फैलाई। उनका आरक्षण सुनिश्चित है। संविधान पीठ ने जिस क्रीमीलेयर की बात कही थी, प्रधानमंत्री ने फिलहाल उसे भी अस्वीकार कर दिया है। दलित और आदिवासियों को सुनिश्चित कौन कर सकता है? क्या कांग्रेस, सपा, राजद, बसपा सरीखी राजनीतिक पार्टियां दलितों और आदिवासियों को बुनियादी तौर पर विश्वास दिला सकती हैं? बहरहाल नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण की सुविधाएं मिल रही हैं। यह उनका मौलिक अधिकार-सा बन गया है। यह दीगर है कि भारत सरकार के कुछ शीर्ष और उच्च पदों पर उनकी भागीदारी 4 फीसदी और 4.5 फीसदी है।

यह परंपरागत विसंगतियों का ही नतीजा है। 2014 में भारतीय सत्ता में बड़ा परिवर्तन हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार शासन में आई थी। सत्ता के 10 सालों में आरक्षण-विरोधी अथवा दलित, आदिवासी-विरोधी एक भी निर्णय सरकार ने नहीं लिया। पहली बार देश के राष्ट्रपति पद पर आदिवासी महिला को आसीन कराया गया। अभी 45 उच्च पदों पर जो सीधी नियुक्तियां की जानी थी, उस फैसले को भी वापस ले लिया गया। विपक्ष कुछ भी व्याख्या करता रहे। बेशक भाजपा की तुलना 'विषैले सांप' से करता रहे। सवाल है कि दलित, आदिवासी संगठनों को कोई ठोस शिकायत है अथवा वे राजनीतिक नेरेटिव से संचालित किए जा रहे हैं? जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं, जिन्हें लगता है कि वे आरक्षण, संविधान बचाने के मुद्दे पर मोदी और भाजपा का राजनीतिक विस्तार रोक सकते हैं, वे 'भारत बंद' के दौरान कहां थे? सडक़ पर मायावती, अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सरीखे नेता दिखाई नहीं दिए, जो आजकल दलित, आदिवासियों और पिछड़ों के पैरोकार बने हैं। यदि संगठनों को संविधान पीठ के फैसले पर आपत्ति थी, तो वे सर्वोच्च अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते थे। संविधान पीठ कोई

राजनीतिक संगठन नहीं है, जिसके खिलाफ 'भारत बंद' के जरिए विरोध-प्रदर्शन किया जाए। वह न्याय का सर्वोच्च और अंतिम मंच है। मोदी सरकार ने ऐसा कुछ किया नहीं है कि 'भारत बंद' का आह्वान किया जाता। पंजाब और हरियाणा में कुछ दलित जातियां ऐसी हैं, जिन्होंने 'भारत बंद' का समर्थन नहीं किया। वाल्मीकि और मजहबी सिख आदि आरक्षण के उप वर्गीकरण के पक्षधर हैं। दलित और आदिवासियों को एहसास होना चाहिए कि उच्च जातियां उनके आरक्षित पदों को नहीं हड़प रही हैं, बल्कि ऐसे पद भरे ही नहीं जा रहे हैं। आरक्षण में भी कुछ जातियों का वर्चस्व है, जो कमोबेश 50 फीसदी तक आरक्षण वसूल कर लेती हैं और छोटी, हाशिए पर पड़ी जातियां खाली हाथ ही रहती हैं। यह व्यवस्था का ही दोष है। यदि दिल्ली विश्वविद्यालय में 100 साल के कालखंड में मुसलमान सहित उच्च जातियों के चेहरे ही कुलपति बने। दलित, आदिवासी को अवसर ही नहीं मिला। यही हाल बीएचयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रहा है। 'भारत बंद' का मौजूदा मुद्दा ही नहीं था। यदि आरक्षित जातियां अन्य पिछड़ी और वंचित जातियों को आरक्षण के जरिए सम्पन्न और शिक्षित नहीं करना चाहतीं, तो यह दलितों और आदिवासियों के ही अंतर्विरोध हैं। वैसे इस बात का क्या औचित्य है कि आरक्षण के कारण जो दलित और आदिवासी संपन्न हो चुके हैं, उन्हें इस दायरे से बाहर न किया जाए।

राय

## आर्थिक डेस्टिनेशन-6

हिमाचल के आर्थिक सपने प्राकृतिक संसाधनों की विरासत में देखे ही नहीं गए। खेती और बागबानी के मौजूदा स्वरूप में परिवर्तन लाने की जरूरत है, जबकि वन संपदा को चीड़ के पौधों से निजात दिला कर आर्थिक संसाधन बढ़ाए जा सकते हैं। मसलन चाय की खेती का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए जंगल में जमीन खोजी जाए, तो कांगड़ा, चंबा व मंडी के कुछ क्षेत्रों में क्रांति लाई जा सकती है। इसी तरह कॉफी उगाने के प्रयास कुछ क्षेत्रों में सफल हुए हैं, तो हमारे जंगलों में पौधारोपण की परिभाषा बदलनी होगी। वन खेती के लिए हिमाचल का वातावरण राष्ट्रीय आर्थिकी की नई पहल हो सकती है, क्योंकि पारंपरिक जड़ी-बूटियों का वैज्ञानिक उत्पादन हमें चीन के मुकाबले खड़ा कर सकता है। वहां दस से पंद्रह हजार करोड़ की आर्थिकी जड़ी-बूटियों के बाजार को समृद्ध कर रही है। हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने से रोक रहे जंगल को अब नया स्वरूप देने की जरूरत है, लेकिन इसके लिए प्रदेश को अपने संघर्ष और संभावनाएं बदलने होंगे। प्रदेश में आर्थिक विकास के लिए 'भूमि बैंक' की संभावनाओं को लेकर एक नीति बनानी होगी। हर गांव-कस्बे से शहर तक अपने-अपने लैंड बैंक स्थापित करने होंगे। इसके लिए तमाम शहरों का वर्गीकरण करते हुए, इनकी विशिष्टता को देखते हुए निवेश करना होगा। उदाहरण के लिए टांडा मेडिकल कालेज की स्थापना ने कांगड़ा शहर को मेडिकल सिटी बना दिया है। इस तथ्य को समझते हुए अगर निजी निवेश के तहत आगे की संभावनाएं तराशी जाएं, तो कांगड़ा शहर का विकास हिमाचल को मेडिकल टूरिज्म की दिशा में आगे बढ़ा सकता है। विडंबना यह है कि कभी शिक्षा हब जैसे लक्ष्य सामने आए, लेकिन हम इस पहल को राष्ट्रीय मंच का मसौदा नहीं बना पाए।

प्रदेश की कई सरकारी इमारतें शिक्षा व चिकित्सा का दम घोंट रही हैं, तो कोशिश यह होनी चाहिए कि शिक्षण व चिकित्सा संस्थानों के असफल अध्यायों को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रमों से जोडक़र, निवेश के साथ गुणवत्तायुक्त संस्थाओं की स्थापना की जाए। प्रदेश को फोरलेन परियोजनाओं के साथ कम से कम आधा दर्जन नए शहर, निवेश केंद्र या साइंस सिटी का विकास करना चाहिए ताकि ये आर्थिकी केंद्र के रूप में समृद्ध हो सकें। प्रदेश को चंडीगढ़ के समीप बीबीएन क्षेत्र में शहरीकरण की ऊर्जा तलाश करनी चाहिए। अगर औद्योगिक क्षेत्र से आवासीय शहर की परिकल्पना को भी पूरा करें, तो आर्थिकी के कई मजमून स्थापित होंगे। इसी तरह ऊना जिला में हिमाचल को प्रदेश का सबसे आधुनिक शहर बसाना चाहिए जिसके तहत कई औद्योगिक पार्क भी विकसित होंगे। बल्क ड्रग पार्क को अगर हम निवेश की एक हद तक देखें, तो शायद ही पूर्ण क्षमता का दोहन होगा, लेकिन इसके साथ आधुनिक शहर बसा दें, तो आर्थिकी का स्थायित्व पैदा होगा। आर्थिकी के सपनों में हिमाचल को पार्टनर ढूंढने पड़ेंगे, वरना चार दिनों की चांदनी में निवेशक के कदम लौट जाएंगे। बीबीएन में यही हुआ और हो रहा है। पहली बार धूमल सरकार ने निवेशक को हिमाचली बनने का अवसर देते हुए उन्हें डोमिसाइल प्रमाण पत्र देने की घोषणा की थी। इसी तरह आज भी धारा 118 एक औजार की तरह इस्तेमाल होती है, जबकि निवेश मैत्री माहौल के लिए इसकी व्यावहारिकता में सुधार होना चाहिए।

# शिक्षा विभाग राज्य में खेलों को बढ़ावा देगा?

भूपिंद्र सिंह

**प्रधानाचार्यों व शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को चाहिए कि वे अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं'**

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने तीन वर्ष पहले अपने पूर्व में रहे खिलाड़ी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों के लिए एक पत्र निकाला था। इस पत्र में शिक्षा निदेशालय ने शौकिया प्रशिक्षण करवाने वाले इच्छुक शिक्षकों व कर्मचारियों के नाम मांगे थे ताकि उन्हें प्रशिक्षण सुविधाओं वाली जगहों पर नियुक्त किया जा सके। मगर आज तक भेजे गए उन नामों का कुछ पता नहीं चला कि उनका क्या हुआ। अब शिक्षा निदेशालय एक बार फिर अपने पूर्व में रहे खिलाड़ी शिक्षकों व अन्य कर्मचारियों से स्कूल के बाद खेल प्रशिक्षण दिलाने के बारे में सोच रहा है। देखते हैं कब तक इस कार्य को अमलीजामा पहनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों खिलाड़ी खेल आरक्षण के अंतर्गत विभिन्न विभागों में नौकरी कर रहे हैं। दर्जन भर खिलाडियों को छोड़ कर न तो कोई खेल कर रहा है और न ही प्रशिक्षण व अन्य खेल प्रबंधन से जुड़ा है। खेलों से नियमित रोजी-रोटी मिलने वालों को चाहिए कि वे नमक का कुछ तो हक अदा करें। अगर खिलाड़ी के रूप में नहीं हो सकता है तो प्रशिक्षण व प्रबंधन तो आसानी से हो ही सकता है। हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के विभिन्न विभागों में खेल आरक्षण के अंतर्गत तीन प्रतिशत पदों पर भर्ती करती है।

शिक्षा विभाग में अब तक सैंकड़ों प्रवक्ता, प्रशिक्षित स्नातक व अन्य पदों पर खेल आरक्षण से शिक्षक नियुक्त हैं। हिमाचल प्रदेश का हर बच्चा विद्यालय जा रहा है। वैसे तो विद्यालय में विद्यार्थियों की फिटनेस व खेलों के लिए शारीरिक शिक्षा का शिक्षक नियुक्त होता है, मगर वह हर खेल के लिए प्रशिक्षण नहीं दे सकता है। भविष्य के अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी तैयार करने के लिए किशोरावस्था से ही सही तकनीक के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम का महत्व बढ़ जाता है। अरबों की आबादी में किसी खेल विशेष में सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए क्षमतावान प्रशिक्षक का प्रारंभिक स्तर से होना बेहद अनिवार्य हो जाता है, जो सही उम्र में सही तकनीक सिखा कर भविष्य में खिलाड़ी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। हिमाचल प्रदेश में खेल प्रशिक्षण के लिए शुरू से वह वातावरण ही नहीं बन पा रहा है, जिससे बाद में प्रशिक्षक खिलाड़ी से राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठतम परिणाम दिला सके। खेल प्रशिक्षण दस साल से भी अधिक समय तक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इतने लंबे खेल प्रशिक्षण को प्राप्त कर कुछ एक खिलाड़ी ही अपने प्रदेश व देश को गौरव दिला पाते हैं। हिमाचल प्रदेश में विद्यालय स्तर पर शारीरिक शिक्षकों की कमी सबके सामने है। विद्यालय जीवन ही वह समय है जब खिलाड़ी तकनीक को सीख रहा होता है। हिमाचल प्रदेश में लगातार प्रशिक्षण के लिए विद्यालय खुलने से पहले व बंद होने के बाद हिमाचल प्रदेश में शारीरिक शिक्षकों को छोड़ कर अन्य विषयों के शिक्षक जो पूर्व में अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, अपने पढ़ाई के कार्य के साथ-साथ विभिन्न खेलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला कर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश व देश का नाम पूर्व में रोशन करते रहे हैं और वर्तमान में कर भी रहे हैं। हमीरपुर शहर के वरिष्ठ माध्यमिक कन्या राजकीय विद्यालय में चार दशक पूर्व नियुक्त प्रयोगशाला सहायक अमरनाथ शर्मा ने हमीरपुर से महिला हाकी के लिए निचले स्तर पर बहुत अच्छा काम किया था। इस तरह और कई नाम हैं जिन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ खेल प्रशिक्षण में भी सराहनीय कार्य किया है।

वर्तमान में बिलासपुर जिले के दूरदराज मोरसिंघी गांव के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में राजनीति शास्त्र की प्रवक्ता व पूर्व अंतरराष्ट्रीय हैंडबाल खिलाड़ी स्नेहलता के प्रशिक्षण कार्यक्रम से राष्ट्रीय स्तर पर हर आयु वर्ग की महिला प्रतियोगिताओं में हिमाचल विजेता है। पिछले एशियाड में भारतीय महिला हैंडबाल टीम में चार खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश से थी। इस साल की राष्ट्रीय महिला हैंडबाल प्रतियोगिता की विजेता हिमाचल प्रदेश की टीम में अधिकांश खिलाड़ी मोरसिंघी नर्सरी से हैं। स्नेहलता की पहली नियुक्ति शिक्षा विभाग में सोलन जिले के नवगांव वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में हुई थी। उसी समय से स्नेह लता ने हैंडबाल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। एक दशक पूर्व हमीरपुर जिले के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कक्डयार में नियुक्त प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक कुलवीर सिंह ने एथलेटिक्स में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था। उसके अच्छे परिणाम रहे थे। मगर बाद में ऐसी जगह ट्रांसफर हो गई जहां प्ले फील्ड व समय की दिक्कत के कारण उनका प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद हो गया। हमीरपुर में आज अपने समय के स्टार धावक अनिल शर्मा व रजनीश शर्मा जो दोनों ही प्रशिक्षित स्नातक अध्यापक के पद पर शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी के बाद शाम के समय अणु सिंथेटिक ट्रैक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कई खेलों के खिलाड़ी शिक्षक के पदों पर नियुक्त हैं। हिमाचल शिक्षा विभाग में कई शिक्षक तो राष्ट्रीय स्तर पर कई बार हिमाचल प्रदेश का प्रतिनिधित्व किए हुए व राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान से क्वालीफाईड प्रशिक्षक भी हैं। क्या शिक्षा विभाग उनकी सेवाओं को प्रशिक्षण के लिए लेगा?

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में हायर व एलीमेंट्री निदेशालयों को चाहिए कि वे खेल आरक्षण से नियुक्त शिक्षकों, जो अपनी ड्यूटी के अतिरिक्त अपने खेल में प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं या चलाना चाहते हैं, उन्हें जहां प्ले फील्ड है, वहां नियुक्त करना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा संस्थानों को अच्छे मगर शौकिया प्रशिक्षक मिल सकें जो हिमाचल प्रदेश के खिलाडियों की क्षमता को अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता तक ले जा सकें। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त और विभागों में भी कई खिलाड़ी सरकारी नौकर अपनी नौकरी के बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हुए हैं। क्या खेल विभाग के साथ मिलकर इन खिलाड़ी सरकारी कर्मचारियों व अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए मंच उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है। विद्यालय के प्रधानाचार्यों व शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को चाहिए कि वे खेल सुविधा व प्रतिभा के अनुसार अपने विद्यालय में अच्छे प्रशिक्षकों के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएं ताकि हिमाचल के खिलाडियों को विद्यालय में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध हो सके। आज हिमाचल प्रदेश के कई विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की खेलों के लिए स्तरीय प्ले फील्ड उपलब्ध है। शिक्षा मंत्रालय जब खिलाड़ी अध्यापकों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रोत्साहित करेगा तो निश्चित ही सही तकनीक का प्रशिक्षण मिल सकेगा।

# आजाद तोते की राम कहानी

मैंने ही क्या, उस तोते को मेरे पिताजी ने ही पाल रखा था। मेरे घर के पिंजरे में तोता चने की दाल चुगता और पानी पीकर वर्षों से मेरा प्रिय तोता हो गया था। तोता पालने का मुझे शौक भी था और उससे मिलने वाली सूचनाओं से मैं चौकस भी रहता था। तोता भी खुश था, उसे किसी प्रकार की परेशानी नहीं थी। एक दिन कुछ पर्यावरण प्रेमी मेरे घर के बाहर आए और नारेबाजी करने लगे। मैं और मेरी पत्नी घबराए से बाहर आए। देखा तो पंद्रह-बीस लोग हाथों में तख्ती थामे तोते की आजादी के लिए मुझसे मांग कर रहे थे। मैंने छद्म पर्यावरण प्रेमियों से कहा भी कि तोता मेरे पुरखों ने पाला है और वह मेरे यहां आराम में है। लेकिन उन्होंने तोते को नहीं छोडने पर कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। पत्नी और मैं दोनों भौंचक्के रह गए। मैंने पत्नी से पूछा -'बोलो, क्या करें?' पत्नी ने मुझे आंख मारकर कहा -'जनमत का सम्मान करते हुए हम तोते को छोड़ देते हैं।' पर्यावरण प्रेमी खुश हो गए और बोले, 'हमारे सामने ही पिंजरे को खोलो और तोते को आजाद करो।' मैं पिंजरा बाहर ले आया और उसका दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलने के बाद भी तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकला और पिंजरे में ही शोर मचाने लगा। मैंने पर्यावरण प्रेमियों को विवशता से देखा तो उनमें से एक बोला -'हम आजाद करते हैं इसे।' उसने आगे बढक़र तोता हाथ में पकड़ा और हवा में उछाल दिया। वर्षों से पिंजरे में रहने के कारण तोता भली प्रकार से उड़ नहीं पा रहा था और वह पास के ही एक मकान की छत पर हांफ कर बैठ गया। हम और पर्यावरण प्रेमी उसकी अगली उड़ान की प्रतीक्षा करने लगे।

दस-पंद्रह मिनट बाद में तोते ने पंख फैलाए और आसमान में गायब हो गया। पर्यावरण प्रेमी खुश होकर चले गए। लेकिन हमारा मन अवसाद से भर गया। रह-रह कर तोते की याद सता रही थी। उसकी उपयोगिता पर हम इतने निर्भर हो गए थे कि हमें लगा कि अब हमारा जीवन कैसे चलेगा। आखिर में पत्नी ने कहा -'चलो देखते हैं, आगे का

जीवन कैसे चलता है। चिंता मत करो, कोई न कोई रास्ता अवश्य निकल आएगा।' इसी भावना से हम अपना रहा-सहा समय निकालने लगे। सौभाग्य से मैंने वह पिंजरा फेंका नहीं था और उसका दरवाजा खोल रखा था। अचानक एक दिन तोता उड़ता-उड़ता आया और पुनः पिंजरे में आ बैठा। मैं और मेरी पत्नी बहुत खुश हुए कि हमारा तोता हमारे पास वापस लौट आया है। मैंने भरे मन से तोते से कहा -'यार मिट्ठू तुम आ तो गए, लेकिन वे लोग फिर आ जाएंगे और मुझे व्यर्थ में बदनाम करेंगे।' तोता परेशान सा बोला -'नही, मैं नहीं जाऊंगा। वे लोग मुझे आजाद करने के बहाने अब अपने पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। वे मेरे पीछे पिंजरा लेकर भागे फिर रहे हैं।' तोते की बात सुनकर हम घबरा गए। मैंने कहा -'भाई तुम आकाश में ऊंची उड़ान भरो और गायब हो जाओ। वरना वे लोग इधर आने वाले होंगे।' तोता पिंजरे से बाहर नहीं निकला तो मैंने उसे जीवन सूत्र दिया और कहा -'ऐसा करो मेरे प्यारे मिट्ठू, तुम कभी हमारे पिंजरे में तो कभी उनके पिंजरे में रह लो। इससे तुम्हारा जीवन आराम से निकलता रहेगा। वरना वे लोग मुझे और तुम्हें बदनाम कर देंगे।' तोते को मेरी बात समझ में आ गई और बोला -'यह ठीक है, पिंजरे का दरवाजा खुला रखो, उनका शोर सुनकर मैं उनके पिंजरे में जा बैठूंगा।' मुझे भी बात जंच गई कि तोते को आजादी देने का यह सूत्र सबसे सफल है। अभी तोता मेरे यहां ही है। आगे देखते हैं क्या होता है?

# ई-कॉमर्स नीति में बदलाव करना जरूरी, ज्यादा देर करना उपभोक्ता के हित में नहीं

परिवहन विशेष न्यूज

सामान पसंद नहीं आने पर ई–कॉमर्स कंपनियां सामान लौटा देती हैं लेकिन आप यह जानकार हैरान रह जाएंगे कि अभी कानूनी रूप से ये कंपनियां सामान लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। पहल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में देश के कुल खुदरा कारोबार में ई–कॉमर्स की हिस्सेदारी 10 .4 प्रतिशत हो जाएगी और वर्ष 2030 तक देश में ई–कॉमर्स का आकार 350 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

**नई दिल्ली।** दो दिन पहले वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ई-कॉमर्स को लेकर जो चिंता जताई थी वह उपभोक्ता और छोटे दुकानदार दोनों के हितों लिए जायज थी। छोटे दुकानदार ई-कॉमर्स कंपनियों की गैर प्रतिस्पर्धात्मक रवैये से प्रभावित तो हो ही रहे हैं। कारोबार बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं के साथ ई-कॉमर्स कंपनियों की ठगी भी बढ़ रही है। हालांकि, उपभोक्ता ऑफलाइन व्यापारियों के यहां भी ठगे जाते हैं। नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर वर्ष 2018 में ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ 95,270 शिकायतें आईं जो वर्ष 2023 में बढ़कर 4.44 लाख हो गई।

चिंतित उपभोक्ता मामले का विभाग ई-कॉमर्स कंपनियों को अपना एक लिखित संहिता तैयार करने के लिए कहा है ताकि यह पता लग सके कि कंपनी में क्या मान्य है और क्या अमान्य। ई-कॉमर्स नीति के अभाव में उत्पाद के फेक रिव्यू, उत्पाद की कमी दिखाकर दबाव पैदा करना, उत्पाद की सही जानकारी नहीं देना, सामान लौटाने में आनाकानी करना जैसी हरकतों से उपभोक्ता प्रभावित हो रहे हैं तो सस्ते दाम पर सामान बेच कर, ई-कॉमर्स प्लेटफार्म चलाने वाली कंपनियों की तरफ से अपने उत्पाद बेचने जैसे गैर पेशेवर हरकतों से छोटे दुकानदारों की दुकानदारी खराब हो रही हैं। लेकिन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि अभी हमारे देश में नियम नहीं है। कोई नीति नहीं है।

सामान पसंद नहीं आने पर ई-कॉमर्स कंपनियां सामान लौटा देती हैं, लेकिन आप यह जानकार हैरान रह जाएंगे कि अभी कानूनी रूप से ये कंपनियां सामान लौटाने के लिए बाध्य नहीं है। पहल इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2024 में देश के कुल खुदरा कारोबार में ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी 10.4 प्रतिशत हो जाएगी और वर्ष 2030 तक देश में ई-कॉमर्स का आकार 350 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगा।

ऐसे में पिछले चार साल से 27 प्रतिशत की दर से बढ़ने वाले ई-कॉमर्स के लिए लिखित कानून का होना बहुत जरूरी है। वर्ष 2015-16 में ऑनलाइन मोबाइल फोन की खरीदारी का चलन तेजी से बढ़ा और तब यह शिकायत आने लगी कि फोन की जगह ईंट-पत्थर कंपनियां भेज रही हैं। मामले को सरकार के सामने लाए जाने पर शुरू में यह कहा गया कि उपभोक्ता मामले का मंत्रालय ई-कॉमर्स नियम को देखेगा।

बाद में उपभोक्ता के साथ खुदरा व्यापारी जब बिग बिलियन सेल के खिलाफ आवाज उठाने लगे तो यह तय हुआ कि ई-कामर्स व्यापार से जुड़ा है, इसलिए वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ई-कामर्स नीति को तैयार करेगा। वर्ष 2019 में का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने नेशनल ई-कॉमर्स नीति के लिए मसौदा जारी किया जिसमें ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस, नियामक संबंधी मामले, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, डाटा विकास व सुरक्षा घरेलू डिजिटल कारोबार जैसे मुद्दों को शामिल किया गया था।

लेकिन, उस ड्राफ्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका और उसके बाद ई-कॉमर्स नीति पर एक नेशनल फ्रेमवर्क बनाने की कवायद शुरू हुई। इस साल लोक सभा चुनाव से पहले विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वाणिज्य व उद्योग मंत्री सभी की तरफ से यह बताया गया था कि ई-कॉमर्स नीति तैयार है। छोटे कारोबारियों से लेकर उपभोक्ता तक को इस नीति का इंतजार है।

## भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.54 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ा

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां जो भंडार का एक प्रमुख घटक है 3 .609 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 591 .569 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो पाउंड और येन जैसी गैर–अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है।

**मुंबई।** आरबीआई ने शुक्रवार को कहा कि 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.546 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 674.664 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 4.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर घटकर 670.119 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया था। 2 अगस्त को समग्र भंडार 674.919 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया।

शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, 16 अगस्त को समाप्त सप्ताह में, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, जो भंडार का एक प्रमुख घटक है, 3.609 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 591.569 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। डॉलर के संदर्भ में व्यक्त विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में विदेशी मुद्रा भंडार में रखे गए यूरो, पाउंड और येन जैसी गैर-अमेरिकी इकाइयों की सराहना या मूल्यह्रास का प्रभाव शामिल है।

आरबीआई ने कहा कि सप्ताह के दौरान स्वर्ण भंडार 865 मिलियन डॉलर बढ़कर 60.104 बिलियन डॉलर हो गया। विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) 60 मिलियन डॉलर बढ़कर 18.341 बिलियन डॉलर हो गए। सप्ताह के दौरान आईएमएफ के साथ भारत की आरक्षित स्थिति 12 मिलियन डॉलर बढ़कर 4.65 बिलियन डॉलर हो गई।

## RBI ने यूपी की इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया कैंसिल, पेमेंट में गड़बड़ी से जुड़ा है मामला

ऑडिट के अनुसार 31 मार्च 2021 तक NBFC नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना कर रही थी और अपने ऋणदाताओं को 49 .27 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने में चूक गई थी। आरबीआई ने कहा कि कंपनी बैंक द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रही और साइट पर निरीक्षण के दौरान खातों की किताबें या अन्य दस्तावेज पेश करने में सहयोग करने से इनकार कर दिया।




**मुंबई।** आरबीआई ने कंपनी का रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए कहा कि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी एनबीएफसी-एमएफआई के लिए निर्धारित न्यूनतम नियामकीय शुद्ध स्वामित्व निधि पांच करोड़ रुपये और न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) 15 प्रतिशत पर बनाए रखने में विफल रही।

ऑडिट के अनुसार, 31 मार्च, 2021 तक NBFC नकदी प्रवाह के मुद्दों का सामना कर रही थी और अपने ऋणदाताओं को 49.27 करोड़ रुपये का पुनर्भुगतान करने में चूक गई थी। केंद्रीय बैंक ने कहा-

इसके अलावा, ऑडिटरों ने पाया है कि घाटे (187 करोड़ रुपये) और नेट NPA (82.37 करोड़ रुपये) के कारण भौतिक अनिश्चितता है, जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करती है।

इसके अलावा, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने में देरी देखी गई, क्योंकि इसे लगभग सात महीने बाद 22 अक्टूबर, 2021 को अंतिम रूप दिया गया था। आरबीआई ने कहा कि पर्यवेक्षी रिटर्न जमा करने में काफी देरी हुई।

नहीं पेश की जरूरी जानकारी

आरबीआई ने कहा कि कंपनी बैंक द्वारा मांगी गई आवश्यक जानकारी प्रस्तुत करने में विफल रही और साइट पर निरीक्षण के दौरान खातों की किताबें या अन्य दस्तावेज पेश करने में सहयोग करने से इनकार कर दिया। इस बीच, आरबीआई ने एनडीएक्स पी2पी प्राइवेट लिमिटेड और इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पर 'पीयर-टू-पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म' के कुछ प्रावधानों और डिजिटल लेंडिंग पर दिशानिर्देशों का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने एक बयान में कहा कि इनोफिन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (जिसे ₹लेनडेन क्लबब₹ भी कहा जाता है) पर 1.99 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एक अन्य बयान में कहा गया कि एनडीएक्स पी2पी प्राइवेट लिमिटेड पर 1.92 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

## गलत पते पर कर दिया यूपीआई पेमेंट, RBI ने बताया अब कैसे मिलेगा पैसा वापस

परिवहन विशेष न्यूज

कई बार जल्दबाजी में हम गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट कर देते हैं। ऐसे में पेमेंट को कैसे पाएं ये सवाल मन में आता है। गलत यूपीआई ट्रांजेक्शन को लेकर आरबीआई ने भी नई गाइडलाइन्स जारी की है। अब 24 से 48 घंटे के भीतर पैसे वापस आ जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ तरीकों को भी अपना सकते हैं। आइए आर्टिकल में जानते हैं।

**नई दिल्ली।** डिजिटल पेमेंट (Digital Payment) ने भले हमारी जिंदगी को एक हद तक आसान कर दिया है। अब हम चुटकी में लाखों रुपये का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट को आसान बनाने में यूपीआई (UPI) की अहम योगदान है।

अब आसानी से क्यू आर कोड स्कैन (QR Code) करके या फिर मोबाइल नंबर दर्ज करके हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे में कई बार यूपीआई यूजर जल्दबाजी में गलत यूपीआई आईडी (UPI ID) पर ट्रांजैक्शन कर देते हैं। ऐसे में पैसे वापस लेने में परेशानी होती है।

अगर आपसे भी गलती से गलत यूपीआई आईडी (Wrong UPI Address) पर ट्रांजैक्शन हो जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यूपीआई से गलत ट्रांजेक्शन से जुड़ी चिंता को दूर करने के लिए नई गाइडलाइन्स (RBI New Rules For UPI Payment) जारी की है। नई गाइडलाइन्स के अनुसार अगर गलत यूपीआई आईडी पर पेमेंट हो जाती है तो 24 से 48 घंटों में पैसे वापस मिल सकते हैं।

अगर पैसे भेजने और पाने वाले यूजर एक ही बैंक के कस्टमर हैं तो यह रिफंड कम समय में हो जाएगा। वहीं, अगर दोनों यूजर अलग-अलग बैंक के कस्टमर हैं तब रिफंड प्रोसेस में ज्यादा समय लग सकता है।

**अपनाएं ये तरीका**

इसके अलावा हम आपको कुछ तरीके बताने जा रहे हैं जिसकी मदद से आप आसानी से रिफंड पा सकते हैं।




- आपको सबसे पहले उस व्यक्ति से संपर्क करना चाहिए जिसके पास गलती से पेमेंट चली गई है। आप उस व्यक्ति को पेमेंट का स्क्रीनशॉट शेयर करके पैसे वापस भेजने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं।
- अगर पैसे पाने वाला यूजर रिफंड के लिए मना कर देता है तो आप टोल-फ्री नंबर 1800-120-1740 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- आपने जिस यूपीआई बेस्ड ऐप के जरिये पेमेंट की है उस ऐप के कस्टमर केयर सपोर्ट से बात कर सकते हैं। कस्टमर केयर सपोर्ट से ट्रांजैक्शन डिटेल्स शेयर करें और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
- आप गलत यूपीआई पेमेंट को लेकर अपने बैंक से भी संपर्क कर सकते हैं। पैसे रिफंड करने में बैंक आपकी मदद कर सकता है।
- नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) द्वारा यूपीआई ट्रांजैक्शन मैनेज होता है। आप एनपीसीआई में भी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

इन सभी आसान तरीकों को अपनाकर आप पैसे वापस पा सकते हैं।

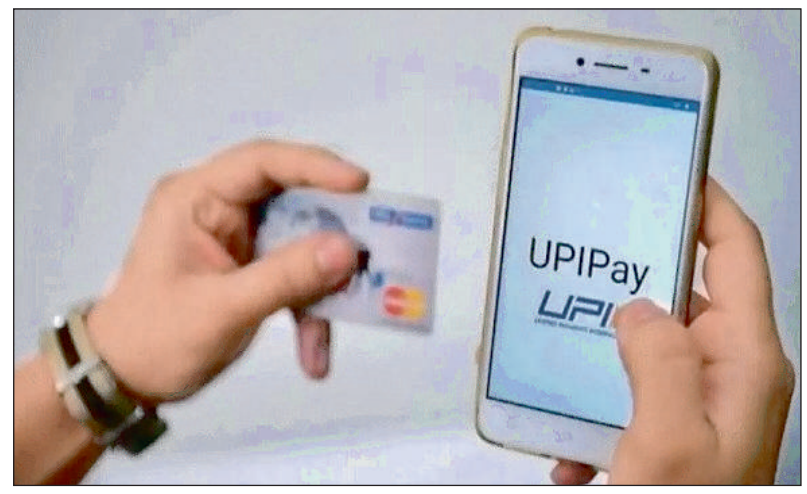

## तूफानी रफ्तार से बढ़ने वाली है बिजली की डिमांड, क्या पावर और सोलर कंपनियों को होगा फायदा?

अगले 6 महीने में पावर डिमांड में तेज उछाल आने का अनुमान है। सरकार भी डिमांड पूरा करने की तैयारी तेज कर रही है। इसके लिए कोयले से बनने वाली परंपरागत बिजली के साथ सोलर और विंड पावर पर भी जोर दिया जाएगा। इसका फायदा पावर और सोलर सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को मिल सकता है जिसका असर नजर उनके शेयरों पर भी आने की उम्मीद रहेगी।

**नई दिल्ली।** देश में बिजली की मांग अगले छह वर्षों में सालाना 15 गीगावाट की दर से बढ़ेगी। यह पिछले एक दशक में 11 गीगावाट प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही थी। यह कहना है अतिरिक्त सचिव विद्युत श्रीकांत नागुलापल्ली का। उन्होंने IEEMA के उद्योग सम्मेलन में कहा कि 2030 तक सौर ऊर्जा घंटों के दौरान लगभग 85 गीगावाट अतिरिक्त मांग और गैर सौर ऊर्जा घंटों के दौरान पीक मांग में 90 गीगावाट से अधिक की वृद्धि होगी।

नागुलापल्ली ने कहा, ₹... सीएजीआर इन संख्याओं को सही रूप से बता सकता, लेकिन पावर डिमांड के मामले यह एक बड़ी छलांग है। इस वृद्धि को पूरा करने के लिए हम कोयला क्षमता और सौर, पवन, भंडारण और ट्रांसमिशन क्षमता का पर्याप्त विस्तार कर रहे हैं।₹ नागुलापल्ली ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में भारत की पीक मांग औसतन 11GW बढ़ी है और अगले 6 वर्षों में औसतन 15 GW प्रति वर्ष बढ़ने का अनुमान है।






**स्टोरेज पर रहेगा सरकार का जोर**

सरकार डिमांड और सप्लाई के बीच संतुलन दूर करने के लिए पावर स्टोरेज पर अधिक जोर देगी। नागुलापल्ली का कहना है कि लगभग 40 GW स्टोरेज के माध्यम से होगी। उन्होंने कहा, ₹2030 तक हमारा इरादा स्टोरेज कैपेसिटी पर निर्भर रहने काहै। फिर चाहे वह हमारे गैर-सौर घंटे के पीक की आपूर्ति के लिए लंबी स्टोरेज बैटरी हो।₹ बिजली मंत्रालय ने 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 500 GW क्षमता का लक्ष्य रखा है।

नागुलापल्ली ने कहा, ₹... हम पहले ही 200 GW (RE क्षमता वृद्धि) को पार कर चुके हैं। अगले 6 वर्षों में अतिरिक्त 300 GW हासिल करना है। इसमें से (300GW) लगभग 225 GW सोलर और विंड से होगा।₹ क्षमता वृद्धि के बारे में उन्होंने कहा कि इस योजना में राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि वहां सौर ऊर्जा की बड़ी क्षमता वाली भूमि उपलब्ध है।

उन्होंने गुजरात और तमिलनाडु तट के पास अपतटीय पवन फार्म स्थापित करने की योजना के बारे में भी बात की और कहा कि देश विशेष रूप से ओडिशा, गुजरात, तमिलनाडु आदि के तटीय क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर हरित हाइड्रोजन क्षमता जोड़ने के लिए कमर कस रहा है।

## वित्त वर्ष 2024 में EPFO योजना के तहत 1.09 करोड़ नए कस्टमर्स जुड़े

कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान कुल 1.09 करोड़ नए EPF ग्राहक जोड़े गए है। वहीं कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत नए पंजीकृत कर्मचारी 1.67 करोड़ थे। अगर राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) की बात करें तो इस अवधि में एनपीएस के तहत नए योगदान देने वाले ग्राहकों की कुल संख्या 973428 थी। आइये इसके बारे में जानते हैं।

**नई दिल्ली।** सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (Ministry of Statistics and Programme Implementation) ने शुक्रवार को कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कुल 1.09 करोड़ नए ईपीएफ ग्राहक जुड़े। यह डेटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जो औपचारिक नौकरी क्षेत्र में अपना रास्ता बना रहे हैं।

सरकार सितंबर 2017 से लेकर अब तक की अवधि को कवर करते हुए औपचारिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित आंकड़े जारी कर रही है, जिसमें तीन प्रमुख योजनाओं, यानी कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना, कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सदस्यता लेने वाले ग्राहकों की संख्या की जानकारी का उपयोग किया गया है।

**ESI से जुड़े 1.67 करोड़ लोग**

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत, नए पंजीकृत कर्मचारी और योजना के तहत अंशदान देने वाले 1.67 करोड़ थे। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान एनपीएस के तहत नए योगदान देने वाले ग्राहकों की कुल संख्या 973,428 थी।

ग्राहकों की संख्या विभिन्न स्रोतों से ली गई है और इसमें ओवरलैप के तत्व हैं। इसलिए, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुमान योगात्मक नहीं हैं। सितंबर 2017 से जून 2024 की अवधि के लिए विस्तृत जानकारी संबंधित संगठनात्मक वेबसाइटों पर अलग से प्रकाशित की जाती है।

मंत्रालय ने कहा कि वर्तमान रिपोर्ट औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तरों पर अलग-अलग दृष्टिकोण देती है और समग्र स्तर पर रोजगार को नहीं मापती है। मंत्रालय सामग्री, कवरेज और प्रस्तुति में सुधार के लिए सुझावों का स्वागत करता है। अगली रिपोर्ट 25 सितंबर, 2024 को जारी होने वाली है।

# 'तटस्थ नहीं भारत, हमेशा शांति के साथ', जेलेंस्की से मुलाकात में बोले पीएम मोदी

यूक्रेन पहुंचे पीएम मोदी ने एक बार फिर से शांति का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हम युद्ध से दूर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तटस्थ रहे हैं। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष शांति का है। राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान भी मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान किया

**नई दिल्ली।** यूक्रेन की यात्रा पर शुक्रवार सुबह कीव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक बार फिर युद्धरत रूस और यूक्रेन को शांति का संदेश दिया है। रूस की यात्रा के ठीक छह सप्ताह बाद यूक्रेन पहुंचे मोदी ने वैश्विक समुदाय को संदेश दिया कि भारत दो वर्षों से चल रहे रूस-यूक्रेन युद्ध में तटस्थ नहीं है। भारत हमेशा शांति के साथ रहा है।

**पीएम मोदी ने रूस-यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का किया आह्वान**

राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान भी मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच सीधी बातचीत का आह्वान किया, ताकि युद्ध को शीघ्रता से समाप्त किया जा सके। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच आधिकारिक वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया गया है। इसमें भारत ने यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता व संप्रभुता के आदर की बात कही है। साथ ही दोनों देशों में सैन्य-तकनीक सहयोग को लेकर संयुक्त कार्य समूह की बैठक फिर से शुरू करने पर सहमति बनी है।

**पीएम मोदी ने यात्रा को बताया ऐतिहासिक**

मोदी ने स्वयं इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया। पहला कारण तो यह है कि वर्ष 1991 में यूक्रेन के स्वतंत्र देश बनने के बाद पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने वहां का दौरा किया है। दूसरा, मोदी ऐसे पहले वैश्विक नेता हैं, जिन्होंने कुछ ही दिनों के अंतर में रूस के साथ यूक्रेन की यात्रा की है। उन्होंने दोनों देशों के राष्ट्रपतियों के साथ न सिर्फ

द्विपक्षीय वार्ता की, बल्कि उन्हें शांति का संदेश भी दिया है।

**पोलैंड से रेल मार्ग से कीव पहुंचे पीएम मोदी**

पोलैंड से रेल मार्ग से कीव पहुंचे पीएम मोदी का राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मौजूदा तनाव भरे माहौल के बावजूद शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने अपने खास अंदाज में उन्हें गले लगाकर अभिवादन किया। दोनों नेताओं ने युद्ध में मारे गए बच्चों की स्मृति में निर्मित संग्रहालय का दौरा किया। वहां प्रदर्शित फिल्म को देख कर पीएम मोदी भावुक भी हुए।

इस बारे में अपने प्रेस वक्तव्य में उन्होंने कहा- 'मैंने आपके साथ बच्चों की स्मृति में बने म्यूजियम को देखा है। मेरा मन भरा हुआ है। दिल को गहरी चोट लगी है। अब मुझे लगता है कि युद्ध का पहला शिकार मानव होता है और उसमें भी बालक पहले शिकार बनते हैं। यह बहुत दर्दनाक होता है। किसी भी सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं को स्वीकार नहीं किया जा सकता।'

**2021 में हुई थी दोनों नेताओं की पहली मुलाकात**

शनिवार (24 अगस्त) को यूक्रेन का राष्ट्रीय दिवस है, जिस पर मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति और वहां की जनता को 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से शुभकामना दी। पीएम मोदी की जेलेंस्की से पहली मुलाकात नवंबर, 2021 में हुई थी और तभी उन्हें यूक्रेन आने का निमंत्रण मिला था।

फरवरी, 2022 से रूस व यूक्रेन में युद्ध चल रहा है। मोदी ने कहा कि तब मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि ऐसी परिस्थिति में यूक्रेन की यात्रा करनी होगी, लेकिन मौजूदा तनावपूर्ण माहौल के बावजूद दोनों देशों के रिश्तों में प्रगति हो रही है जो बताता है कि हम परिपक्वता से रिश्तों पर काम कर रहे हैं।

**राष्ट्रपति जेलेंस्की को मिला भारत आने का न्योता**

मोदी ने भी राष्ट्रपति जेलेंस्की को भारत आने का निमंत्रण दिया और कहा कि इस संकट की घड़ी में भारत ने जितना हो सका है, उतनी मदद का प्रयास किया है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि मानवीय दृष्टिकोण से जिस तरह की भी जरूरत यूक्रेन को होगी, भारत आपके साथ खड़ा होगा और दो कदम आगे चलेगा।

हम युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम तटस्थ रहे हैं। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष शांति का है। उन्होंने कहा कि शांति के लिए भारत हरसंभव मदद को तैयार है। इसके लिए मैं व्यक्तिगत प्रयास भी करूंगा।

## नया पीसीसी अध्यक्ष चुनने में कम से कम डेढ़ महीना और लग सकता है :डा. अजय कुमार

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड उडीशा

**भुबनेस्वर :** नया पीसीसी अध्यक्ष चुनने में कितना समय लगेगा, इसका कोई सटीक पता नहीं है । इसमें कम से कम डेढ़ महीना और लग सकता है । लंबी प्रक्रिया के बाद पीसीसी अध्यक्ष का चयन किया जाएगा । प्रदेश के 314 ब्लॉकों में कांग्रेस नेताओं की राय के आधार पर पीसीसी अध्यक्ष का चयन किया जाएगा ।प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ. अजय कुमार हालांकि, जब तक पीसीसी कमेटी का गठन नहीं हो जाता, तब तक राज्य में सभी कार्यक्रमों का संचालन संचालन समिति ही करेगी । जरूरत पड़ने पर मैनेजर जूम मीटिंग में मिलेंगे । कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि गुरुवार शाम कांग्रेस भवन में बैठी प्रदेश कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक में ऐसा निर्णय लिया गया ।

इसी तरह आने वाले दिनों में कांग्रेस विधानसभा और बाहर विभिन्न मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेगी । निर्णय लिया गया है कि गंजम में शराब के नशे में हुई मौतों, कानून व्यवस्था की स्थिति, कीमतों में बढ़ोतरी आदि के मुद्दे को व्यापक बनाया जाएगा। संचालन समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष अजय कुमार ने की जबकि कांग्रेस विधायक दल के नेता रामचंद्र कदम, उपनेता अशोक दास, वरिष्ठ विधायक ताराप्रसाद भागरपति, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष जयदेव जेना, विश्वरंजन मोहंती मेजर ने भाग लिया ।

## क्या है भीष्म क्यूब, जिसे पीएम मोदी ने जेलेंस्की को किया गिफ्ट; पढ़ें इस तोहफे की खासियत

पीएम मोदी ने अपने यूक्रेन दौरे के दौरान राष्ट्रपति राष्ट्रपति जेलेंस्की को चार भीष्म क्यूब गिफ्ट किया। इनका उपयोग युद्ध में घायल आम जनता के साथ ही सैनिकों को तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने में किया जा सकता है ।राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया है। मालूम हो कि 36 छोटे चिकित्सा पैकेटों को मिलाकर एक मदर क्यूब और दो मदर क्यूब से एक भीष्म क्यूब बनाया जाता है।

**नई दिल्ली।** युद्धग्रस्त यूक्रेन को भारत ने शुक्रवार को वह दिया, जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। यह चीज है कि आपातकाल में इस्तेमाल होने वाली चिकित्सा सामग्रियों का किट। इस किट को भारत ने खास तौर पर विकासशील देशों को चिकित्सा क्षेत्र में मदद देने के लिए शुरू किए गए प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री के तहत तैयार किया है और इसका नाम भीष्म रखा गया है।

**कैसे बनता है भीष्म क्यूब ?**

इसके तहत दवाइयों, मरहम-पट्टी, इंजेक्शन आदि का एक छोटा 15 इंच का चिकित्सा पैकेट होता है। इस तरह के 36 छोटे चिकित्सा पैकेटों को मिलाकर एक मदर क्यूब बनाया जाता है और दो मदर क्यूब को मिलाकर एक भीष्म क्यूब बनाया जाता है।

**पीएम मोदी ने यूक्रेन को दिया चार भीष्म क्यूब**

पीएम नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की को इस तरह के चार भीष्म क्यूब सौंपे। इनका उपयोग युद्ध में घायल आम जनता के साथ ही सैनिकों को तत्काल चिकित्सा सहायता पहुंचाने में किया जा सकता है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसके लिए भारत को धन्यवाद दिया है।

**दोनों देशों के बीच हुए चार समझौते**

बाद में जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई, उसमें भी चिकित्सा व मेडिकल क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाने को लेकर बात हुई है। दोनों देशों के बीच चार समझौते हुए हैं, जिनमें एक समझौता स्वास्थ्य व ड्रग्स को लेकर है। इससे भारतीय दवाइयों व चिकित्सा उपकरणों को यूक्रेन निर्यात करने की राह आसान होगी।

**आर्थिक व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग पर भी बनी बात**

अन्य समझौते कृषि व खाद्य प्रसंस्करण, भारत की तरफ से सामुदायिक विकास के लिए यूक्रेन को अनुदान देने और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने को लेकर है। दोनों देशों के बीच आर्थिक व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने को लेकर भी सहमति बनी है। इस संबंध में भारत-यूक्रेन के बीच अंतर-सरकारी आयोग का गठन पहले ही हो चुका है और इसकी एक बैठक मार्च, 2024 में हुई थी।

यह आयोग कारोबार, वाणिज्य, औद्योगिक, संस्कृति, विज्ञान व तकनीकी क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बनाने और उनको लागू करने का काम करता है। इसकी अगली बैठक इस साल के अंत तक होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया कि दोनों नेताओं के बीच हुई बैठक में आपसी सहयोग से जुड़े मुद्दों के अलावा रूस से तेल खरीद का मुद्दा भी उठा।

## भाजपा जिला स्तरीय सदस्यता महा अभियान की कार्यशाला आज

भाजपा वृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ 1 सितंबर को होगा

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

**भीलवाड़ा।** भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार भाजपा वृहद सदस्यता महा अभियान का शुभारंभ 1 सितंबर को किया जाएगा, जिसके तहत भाजपा के वृहद सदस्यता अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 24 अगस्त शनिवार प्रातः 10 बजे भाजपा जिला कार्यालय, टंकी के बालाजी के सामने भीलवाड़ा पर आयोजित होगी, भाजपा सदस्यता अभियान कार्यशाला भाजपा प्रदेश महामंत्री जितेंद्र गोठवाल के मुख्य वक्ता एवं मुख्य अतिथ्य, भाजपा सांसद व प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल के सानिध्य एवं भाजपा जिला अध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा की अध्यक्षता में आयोजित होगी,

जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि भाजपा के वृहद सदस्यता अभियान का शुभारंभ 1 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रथम सदस्य बनकर करेंगे इसके पश्चात संगठन द्वारा देश भर में जिला स्तर से लेकर बुथ स्तर तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, 25 से 31 अगस्त तक मंडल एवं बूथ स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी सदस्यता महा अभियान कार्यशाला में राष्ट्रीय प्रदेश पदाधिकारी ,प्रदेश सदस्यता अभियान सहसंयोजक ,जिला संगठन प्रभारी सह प्रभारी, विधायक ,पूर्व सांसद विधायक, जिला पदाधिकारी ,प्रदेश मोर्चा प्रकोष्ठ पदाधिकारी सदस्य, जिला सदस्यता अभियान संयोजक सहसंयोजक मंडल संयोजक सहसंयोजक ,जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख पूर्व जिला प्रमुख, पूर्व भाजपा जिला महामंत्री ,विधानसभा संयोजक प्रभारी समन्वयक ,मोर्चा जिला अध्यक्ष महामंत्री ,मंडल अध्यक्ष मंडल महामंत्री ,मंडल प्रभारी, प्रधान उप प्रधान ,चेयरमैन वाइस चेयरमैन नेता प्रतिपक्ष ,जिला कार्य समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य ,जिला प्रकोष्ठ संयोजक, विभाग संयोजक, पंचायत समिति सदस्य , समस्त पार्षद गण भाग लेंगे।

## त्रिपुरा में बाढ़ से हाहाकर, अब तक 22 लोगों की मौत

त्रिपुरा में लगातार बारिश से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए हैं जिससे 17 लाख लोग प्रभावित हैं। अब तक बाढ़ से 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 65 हजार से भी अधिक लोग राहत शिविरों में रहने पर मजबूर हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है।

**नई दिल्ली।** त्रिपुरा में लगातार बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति गंभीर बन गई है। बाढ़ में 22 लोगों की मौत हो गई है और दो अन्य लापता हैं। बुनियादी ढांचे, फसलों और पशुधन को भी भारी नुकसान हुआ है। राज्य में 65,400 लोगों ने 450 राहत शिविरों में शरण ली है, क्योंकि भारी बारिश के कारण उनके घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं।

पूर्वोत्तर राज्य में बाढ़ से करीब 17 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने मृतकों के परिवारों के लिए 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि की घोषणा की है। केंद्र ने बाढ़ प्रभावित त्रिपुरा के लिए 40 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन के बाद शुक्रवार को भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में जीवनरक्षक नौकाओं में सवार सैनिकों ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया।

**थमा बारिश का सिलसिला**

कारें और बसें सड़कों पर घुटनों तक पानी में फंसी हुई थीं। शुक्रवार की सुबह से स्थिति में कुछ सुधार के संकेत दिखे हैं, गुरुवार को भारी बारिश का सिलसिला थम गया है, जिससे गुमती, खोवाई, फेनी सहित प्रमुख नदियों के जल स्तर में कमी आई है, जो उफान पर थीं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुशांत चौधरी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में भीषण बाढ़ के बावजूद त्रिपुरा में खाद्य पदार्थों और ईंधन का पर्याप्त भंडार है।

त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने उदयपुर, अमरपुर और कारबुक क्षेत्रों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया और उन्होंने कई राहत शिविरों का भी दौरा भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में राज्य सरकार की सहायता के लिए केंद्र ने एनडीआरएफ की 11 टीम, सेना की तीन टुकड़ियां और भारतीय वायुसेना के चार हेलिकाप्टर तैनात किए हैं।

**गृह मंत्री ने दिया मदद का आश्वासन**

गृह मंत्री ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए त्रिपुरा में हमारे भाई-बहन इस कठिन समय में मोदी सरकार को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा पाएंगे। इससे पहले शाह ने मुख्यमंत्री माणिक साहा से फोन पर बात करके राज्य में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया था और उन्हें केंद्र की ओर से हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया था।

**बांग्लादेश में बाढ़ से 13 लोगों की हुई मौत**

बांग्लादेश के कुछ हिस्सों में आई बाढ़ से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए और कई परिवार विस्थापित हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के कुल 64 जिलों में से 11 में बाढ़ के कारण लगभग 44 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश और पहाड़ियों से पानी के प्रवाह के कारण आई बाढ़ और भूस्खलन देश के कई हिस्सों में मकान, फसल, सड़क और राजमार्गों को भारी नुकसान पहुंचा है। राहत और बचाव के लिए कई केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर करीब 200,000 लोगों ने शरण ली है।

## संगम विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने किया मेनाल वन भ्रमण

परिवहन विशेष अनूप कुमार शर्मा

**भीलवाड़ा।** राजस्थान के मेनाल वन का दौरा संगम विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने किया।

संगम विश्वविद्यालय कि शोधार्थी श्रेया शेखावत और जयंत शर्मा ने हाल ही में डॉ. शाहदाब हुसैन के मार्गदर्शन में ओफियोग्लोसम की पहचान, वार्गिकी और जैव विविधता पर चल रहे अपने शोध के लिए मेनाल वन का दौरा किया। इस दौरान, डॉ. शाहदाब ने शोधार्थी का मार्गदर्शन किया, उन्होंने वन के विभिन्न भागों से ओफियोग्लोसम का पता लगाया, नमूने एकत्र किए और ओफियोग्लोसम की विभिन्न प्रजातियों पर डेटा रिकॉर्ड किया जिसमें कुछ नए प्रजाति भी रिपोर्ट की गई।

एकत्र किए गए डेटा का विश्वविद्यालय में विश्लेषण किया जाएगा और चल रहे शोध परियोजनाओं में योगदान दिया जाएगा, जिनमें से कुछ का उद्देश्य वैज्ञानिक पत्रिकाओं में निष्कर्ष प्रकाशित करना है। यह शोध परियोजना ओफियोग्लोसम की जैव विविधता को समझने और संरक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

संगम विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. शादाब हुसैन ने मेनाल रिजर्व फॉरेस्ट में 14 वर्षों से अनुसंधान कार्य किया है। उन्होंने अपने शोधार्थियों श्रेया शेखावत, अरीबा खान, और जयंत शर्मा के साथ मेनाल रिजर्व फॉरेस्टक्षेत्र में पादपों की विविधता का अध्ययन किया।

इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान, उन्होंने टेरिडोफाइटिक और एंजियोस्पर्मिक पादपों की कई प्रजातियों का एकत्रीकरण और साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन किया। डॉ. शादाब हुसैन ने बताया कि मेनाल रिजर्व फॉरेस्ट की बायोडायवर्सिटी विभिन्न पादप प्रजातियों के लिए एक वरदान है, लेकिन अधिकांश जंगली पादप प्रजातियों को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

इस क्षेत्र में कई पादप प्रजातियां संकटग्रस्त और दुर्लभ हो गई हैं, जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इनमें कई पादप प्रजातियां अत्यधिक औषधीय महत्व की हैं और आयुर्वेदिक विधि से विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है। इस साइंटिफिक स्टडी से इस क्षेत्र को वनस्पति विज्ञान में शोध के लिए एक नई पहचान प्राप्त होगी।

हैदराबाद करमनघाट स्थित अल्मासगुड़ा सीरवी समाज पूर्व सचिव हिरालाल सैणचा निवास स्थान पर आयोजित कजरी तीज अवसर पर विधिया देवी, नारेगी देवी, कमला देवी, पिन्की देवी, संगीता देवी, पुष्पा देवी, सभी ने मिलकर सैणचा निवास पर अपनी पुजा अर्चना कर सभी जुला जुले और चांद देख कर अपना वर्त खोला गया कार्यक्रम में भाग लेती हुईं करमनघाट अल्मासगुड़ा सीरवी समाज की महिलाएं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023